Website : www.mantrabharat.com

जुनून है सच लिखने का

डाक पंजीयन संख्याः-एल-2/9/रजि0/एडी0/119/15-17

हिन्दी दैनिक

मंत्र भारत

संस्करण : लखनऊ
वर्ष : 11
अंक : 226
पृष्ठ : 6
मूल्य : 1.00

लखनऊ-रविवार,14 दिसम्बर 2025

लखनऊ, प्रयागराज,ग्वालियर एवं मुम्बई से एक साथ प्रकाशित एवं गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़ से प्रसारित

3 योगी सरकार का किसानों की आर्थिक समृद्धि पर जोर | 4 जो चीजें हमारे यहां नहीं बनतीं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग | 5 हेमा मालिनी को इस नाम से बुलाते हैं सनी-बॉबी देओल, ड्रीम गर्ल ने खुद

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने पंकज चौधरी के प्रस्तावक

पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे

लखनऊ। केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। शनिवार को उन्होंने लखनऊ में भाजपा कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। चौधरी के अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया। ऐसे में पीएम मोदी-अमित शाह के करीबी चौधरी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है। सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत 10 नेताओं ने चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। अब रविवार को लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान करेंगे। दैनिक भास्कर ने कल ही बता दिया था कि पंकज चौधरी ही यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। इससे पहले, दोपहर ढाई बजे तक यूपी भाजपा अध्यक्ष के नाम पर सस्पेंस बना रहा। सुबह 11 बजे पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति पार्टी दफ्तर पहुंचीं तो अचानक हलचल तेज हो गई थी, जब साध्वी से नए अध्यक्ष को लेकर सवाल किया तो वह मुस्कुराने लगीं। बोलीं- थोड़ी देर में सबकुछ सामने आ जाएगा। डेढ़ बजे पंकज चौधरी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने सस्पेंस और बढ़ा दिया। कहा- अभी पार्टी दफ्तर जा रहा हूं, बाद में पता चलेगा। हालांकि, कुछ देर बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पहली बार बिना नाम लिए नए प्रदेश अध्यक्ष का खुलासा किया। उन्होंने कहा- नए अध्यक्ष 7 बार सांसद रहे हैं। वे अपने समाज में भी लोकप्रिय हैं। उन्होंने पार्टी में अहम जिम्मेदारी निभाई है। स्वतंत्र देव का स्पष्ट इशारा पंकज चौधरी की तरफ था। पंकज चौधरी योगी के गढ़ गोरखपुर से हैं। वह महाराजगंज से 7 बार के सांसद हैं। ओबीसी के कुर्मी बिरादरी से आते हैं। बता दें कि यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति 15 जनवरी 2025 को होनी थी, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव तो कभी यूपी उपचुनाव और फिर बिहार चुनाव के चलते मामला लटकता चला गया।

तिरुवनंतपुरम निकाय चुनाव में बड़ा उलटफेर

एनडीए ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत

यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुका है केरल-मोदी

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग को विजयी बनाने के लिए केरल के लोगों को धन्यवाद दिया है और कार्यकताओं की सराहना करते हुए कहा है कि लोगों को यकीन है कि राज्य की विकास की आकांक्षाओं को राजग ही पूरा कर सकता है। तिरुवनंतपुरम निगम चुनाव में राजग की जीत के बाद पीएम मोदी ने रविवार को सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट में इस जीत को ऐतिहासिक क्षण करार दिया। उन्होंने कहा, पूरे केरल के लोगों का धन्यवाद जिन्होंने राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी और राजग उम्मीदवारों को वोट दिया। केरल यूडीएफ और एलडीएफ से तंग आ चुका है। वे राजग को एकमात्र विकल्प के रूप में देखते हैं जो सुशासन

दे सकता है और सभी के लिए अवसरों के साथ विकसित बना सकता है। धन्यवाद तिरुवनंतपुरम! एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, तिरुवनंतपुरम निगम में बीजेपी-राजग को मिला जनादेश केरल की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण है। लोगों को यकीन है कि राज्य की विकास की आकांक्षाओं को केवल हमारी पार्टी ही पूरा कर सकती है। हमारी पार्टी इस जीवंत शहर के विकास की दिशा में काम करेगी और लोगों के लिए श्ईज ऑफ लिविंगश को बढ़ावा देगी। एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, सभी मेहनती भाजपा कार्यकताओं का धन्यवाद जिन्होंने लोगों के बीच काम किया है, जिससे तिरुवनंतपुरम निगम में शानदार परिणाम सुनिश्चित हुआ है। आज केरल में पीढ़ियों के कार्यकताओं के काम और संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, जिससे आज का परिणाम सच हुआ।

सार संक्षेप

बागपत में किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

बागपतः उत्तर प्रदेश में बागपत जिले के बिहारीपुर गांव में शनिवार को एक किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बागपत कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में ऋषिपाल (56) की गांधी चौक के पास किराना की दुकान है। परिजनों के मुताबिक, ऋषिपाल ने शनिवार सुबह करीब पांच बजे दुकान खोली थी। कुछ देर बाद पहुंचे दो बदमाशों ने सीने में गोली मारकर ऋषिपाल की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वारदात से पहले तीसरे बदमाश ने घटना की रेकी की थी। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि 20 दिन पहले गांव के ही एक व्यक्ति से ऋषिपाल का विवाद हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के घर बदमाशों ने फेंका बम, घटना सीसीटीवी में कैद

कानपुर : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कानून-व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। कानपुर कमिश्नरेट के बरार्दृजरौली इलाके में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भदौरिया के घर पर बदमाशों ने बम फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की। इस सनसनीखेज घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, कार सवार नकाबपोश बदमाश देर रात अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भदौरिया के घर के बाहर पहुंचे और उनके घर को निशाना बनाते हुए बम फेंक दिए। धमाके की आवाज से आसपास के लोग दहशत में आ गए। गनीमत रही कि इस हमले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बदमाशों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए कार की नंबर प्लेट पर कालिख पोत रखी थी, ताकि वाहन की पहचान न हो सके। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिसमें बदमाशों की गतिविधियां साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान करने और उनकी तलाश में जुटी हुई।

दिल्ली में एक्यूआई पहुंचा 400 पार

नयी दिल्लीः दिल्ली में शनिवार सुबह धुंध की मोटी चादर छाई रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक 397 के साथ गंभीर श्रेणी के करीब पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली में कुल निगरानी स्टेशन में से 21 में एक्यूआई 400 से अधिक दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार एक्यूआई वजीरपुर में सबसे अधिक 445, विवेक विहार में 444, जहांगीरपुरी में 442, आनंद विहार में 439 और अशोक विहार व रोहिणी दोनों जगह 437 दर्ज किया गया है। आंकड़ों के मुताबिक एक्यूआई नरेला में 432, पटपड़गंज में 431, मुंडका में 430 और बवाना, आईटीओ एवं नेहरू नगर में 429 दर्ज किया गया। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, चांदनी चौक और पंजाबी बाग में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 423 दर्ज किया गया, जबकि सिरी फोर्ट और सोनिया विहार में यह 424 रहा। सीपीसीबी ने बताया कि बुराड़ी क्रॉसिंग में एक्यूआई 414 दर्ज हुआ, इसके बाद कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में 409, नॉर्थ कैंपस और आरके पुरम में 408-408 तथा ओखला फेज-2 में 404 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, शून्य से 50 के बीच का एक्यूआई को अच्छा, 51 से 100 के बीच संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच अत्यंत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है।

मनरेगा का नाम बदलने पर भड़की कांग्रेस

महात्मा गांधी के नाम से भी सरकार को नफरत: कांग्रेस

नयी दिल्ली : कांग्रेस ने सरकार के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-मनरेगा का नाम बदलने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा कि पूरे देश को मालूम है कि नाम बदलने में मोदी सरकार धुरंधर है लेकिन अब यह भी साफ हो गया है कि उसे सिर्फ पंडित जवाहर लाल नेहरू से ही नहीं बल्कि महात्मा गांधी नाम से भी नफरत है। कांग्रेस ने कहा कि महात्मा गांधी के नाम पर मनरेगा योजना चल रही थी और लंबे समय से इस योजना के तहत गांवों में लोगों को रोजगार मिल रहा है लेकिन अब गांधी शब्द हटाकर सरकार ने योजना का नाम बापू कर दिया है जिससे स्पष्ट हो गया है कि सरकार को गांधी नाम से भी नफरत है। पार्टी संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मनरेगा का नाम बदलने के निर्णय पर कहा, ष्योजनाओं के नाम, कानून के नाम बदलने में मोदी सरकार धुरंधर है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। निर्मल भारत अभियान को स्वच्छ भारत अभियान बनाया, ग्रामीण एलपीजी वितरण कार्यक्रम को उज्ज्वला नाम दिया... पैकेजिंग, ब्रांडिंग और नाम देने में ये धुरंधर है। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को पहले से ही नफरत है लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी उनको नफरत है यह अब दिख रहा है। उन्होंने कहा हैरानी इस बात की है कि पंडित नेहरू से तो इन्हें नफरत है लेकिन महात्मा गांधी से इतनी नफरत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 से चल रही है... इसका नाम आप पूज्य बापू रोजगार गारंटी योजना कर रहे हैं, महात्मा गांधी नाम से क्या दिक्कत है।...वहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के नए नामकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है। कांग्रेस सांसद और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि योजना का नाम बदलना समझ से परे है। शनिवार को संसद परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मनरेगा का नाम बदलने के पीछे मोदी सरकार की मानसिकता क्या है? उन्होंने आगे कहा, पहली बात कि योजना में सबसे पहला नाम महात्मा गांधी जी का है और दूसरी बात ये कि जब भी योजना का नाम बदला जाता है तो उसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च होता है। इस योजना का नाम बदलने का फायदा क्या होगा, ये समझ से परे है। वहीं कांग्रेस के सांसद राजीव शुक्ला ने भी प्रियंका गांधी की बातों का समर्थन किया। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी ने यही मुद्दा उठाया है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है। सरकार का यह ऐसा कदम है, जिसकी जरूरत नहीं है। गुजरात में कई लोगों का नाम बापू है, लेकिन फिर भी इस कदम को उठाया जा रहा है।

संसद पर हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि

शीर्ष नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का लिया संकल्प

नयी दिल्ली : संसद पर वर्ष 2001 में आज ही के दिन किये गये आतंकवादी हमले की 24 वीं बरसी पर शनिवार को यहां देश के शीर्ष नेतृत्व ने इस हमले का मुकाबला करते हुए प्राण न्योच्छावर करने वाले सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धापूर्वक नमन किया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संकल्प लिया। उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सी. पी. राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, अनेक केन्द्रीय मंत्री, सांसद, पूर्व सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह, राज्यसभा के महासचिव पी. सी. मोदी तथा शहीदों के परिजनों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राधाकृष्णन ने अपने संदेश में कहा, मैं देश के साथ मिलकर उन बहादुर सुरक्षाकर्मियों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ, जिन्होंने हमारी संसद की पवित्रता की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। उनका अटूट साहस और सर्वोच्च बलिदान आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़े रहने के हमारे राष्ट्र के संकल्प की एक स्थायी याद दिलाता है। श्री बिरला ने कहा, देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता मात्र औपचारिक घोषणा नहीं, बल्कि यह सशक्त संदेश है कि भारत किसी भी प्रकार की आतंकवादी मंशा के आगे कभी नहीं झुकेगा। पीएम मोदी ने शहीद सुरक्षा कर्मियों के शौर्य को स्मरण करते हुए कहा,आज के दिन हमारा देश 2001 में संसद पर हुए जघन्य हमले में अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीरों को याद करता है। गंभीर खतरे के सामने उनका साहस, सतर्कता और कर्तव्यनिष्ठा अद्भुत थी। भारत उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदैव कृतज्ञ रहेगा। गांधी ने कहा, देश के सम्मान की रक्षा करने वाले शहीद जवानों को कोटि कोटि नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। भारत आपका यह बलिदान हमेशा याद रखेगा और इससे देश प्रेम की प्रेरणा लेता रहेगा।

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में गिरी कोल्ड स्टोरेज की दीवार, तीन मजदूरों की मौत, एक गंभीर

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर जिले के नयनपुर क्षेत्र में शनिवार को मित्तल कोल्ड स्टोरेज परिसर की दीवार अचानक गिरने से वहां काम कर रहे चार मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हादसे में दो मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया तथा एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल है, जिसका अस्पताल में उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कोल्ड स्टोरेज में निर्माण अथवा मरम्मत से जुड़ा कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे वहां मौजूद मजदूरों को संभलने का मौका नहीं मिला और मलबे के नीचे दब गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची। राहत और बचाव कार्य

तत्काल शुरू किया गया और मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकाला गया। हादसे की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर एस जयवर्धन और पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर स्वयं मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रशासन द्वारा घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीन मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। घायल मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में चल रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई है। मृत मजदूरों के परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसे देखते हुए किसी भी संभावित आंदोलन या विरोध प्रदर्शन की आशंका के चलते बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। कलेक्टर जयवर्धन ने कहा कि हादसे के कारणों की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। जिले के डीआईजी प्रशांत ठाकुर ने वार्ता को बताया कि जिला कलेक्टर की ओर से जांच के निर्देश मिले हैं, जांच के बाद आए तथ्यों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

घुसपैठियों के नाम पर मुसलमानों को परेशान कर रही सरकारः शिवपाल

इटावा : उत्तर प्रदेश के इटावा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधने का काम किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों को लेकर सरकार के द्वारा चलायें जा रहे अभियान पर कहा सरकार केवल मुसलमानों को परेशान कर रही है जो मुसलमान 100 साल से ज्यादा से यहां रह रहे हैं जिन्होंने आजादी में भाग लिया है, उनके पास आधार कार्ड पहचान पत्र भी है उनको वो लोग घुसपैठिया बता रहे हैं जिन लोगों ने आजादी में भाग नहीं लिया था। शिवपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार की सरकार बताया उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तब से लगातार भ्रष्टाचार बड़ा है। यह सरकार गरीबों की सरकार नहीं है यह पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों के इशारे पर सरकार चल रही है उनको ही सरकार सुविधायें दे रही है। यहां गरीबों और किसानों को सरकार सुविधा नहीं दे रही है यह भ्रष्टाचार ऊपर से आ रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार उत्तर प्रदेश में पीडीए से घबराई हुई है। क्योंकि प्रदेश में 2027 में होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।

हिमाचल में बर्फबारी... पहाड़ों पर मौसम ने ली करवट

अगले 5 दिनों के लिए आईएमडी का अलर्ट

शिमलाः हिमाचल प्रदेश के ऊंची चोटियों में हल्के बादल छाए रहने का अनुमान जताया है, जिससे शनिवार दोपहर में हल्की बारिश और हिमपात हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राज्य में लगभग दो महीने के अंतराल के बाद ऊंची चोटियों में मौसम के इस बदलाव से शुष्क मौसम से कुछ राहत मिल सकती है। विभाग के अनुसार, रविवार देर रात और अगले दिन तड़के तक मौसम इसी तरह का बने रहने की उम्मीद है। राज्यभर में तापमान में गिरावट भी आ सकती है। जिला-वार पूवार्नुमान के अनुसार लाहौल के केलांग में आज हिमपात होने के

40 प्रतिशत आसार हैं और रविवार को लगभग 35 प्रतिशत, जबकि उदयपुर में इसी अवधि के दौरान 25 से 40 प्रतिशत के बीच हल्का हिमपात होने का अनुमान जताया गया है। इसके विपरीत, स्पीति घाटी में काजा के बड़े पैमाने पर शुष्क रहने की उम्मीद है, जहां ज्यादातर इलाकों में धूप खिली रहेगी और बारिश का अनुमान न के बराबर है। फिलहाल लाहौल और स्पीति के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। राजधानी शिमला में, अधिकतम तापमान आठ से दस डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जिससे निवासियों को ऊनी और थर्मल कपड़े पहनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है। इस बीच मौसम के मद्देनजर राष्ट्रीय राजमार्ग-03 पर ग्रामफू-रोहतांग दर्रा खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-505 पर ग्रामफू-बातल खंड बंद हैं, जिससे लाहौल और स्पीति में सड़क संपर्क प्रभावित हो रहा है। जिला प्रशासन के आदेशानुसार दारचा-सरचू मार्ग भी बंद कर दिया गया है, जबकि दारचा-शिनकुला मार्ग केवल कुछ वाहनों के लिए खुला है। लोस्सर-बातल खंड बंद है, हालांकि सुम्दो-लोस्सर खुला हुआ है। अधिकारियों ने मौसम की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए यात्रियों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। लगभग तीन महीने के लंबे सूखे ने राज्य में पहले ही कृषि और पर्यटन को प्रभावित कर दिया है। कृषि विभाग के अनुसार, केवल 30 से 35 प्रतिशत किसान गेहूं, जौ, सरसों, मटर और आलू की बुवाई कर पाए हैं। ये वह किसान हैं जिनके पास सिंचाई की सुविधा है। अभी शिमला, मनाली और डलहौजी जैसे पर्यटन गंतव्यों में पर्यटकों की संख्या कम देखी गयी है। शिमला में एक टैक्सी चालक सुरेश ने कहा, हम क्रिसमस और नए साल के आस-पास हिमपात होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।ष् उन्होंने कहा कि पर्यटकों की आमद कम होने से उनके कारोबार में भी असर पड़ रहा है और कई चालक इसके चलते अपनी ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालत में 56 हजार से अधिक मामलों का निस्तारण

भदोही।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निदेर्शानुसार शनिवार को जनपद न्यायालय परिसर गरपतहों, ज्ञानपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत का भव्य आयोजन

किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश अखिलेश दूबे द्वारा माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत आमजन को त्वरित, सस्ता और सहज न्याय उपलब्ध कराने का प्रभावी माध्यम है, जिसमें किसी की हार या जीत नहीं होती, बल्कि आपसी सहमति से मामलों का अंतिम समाधान किया जाता है। उन्होंने न्यायिक व बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कर आमजन को लोक अदालत का लाभ दिलाया जाए। राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण हेतु कुल 76,709 मामले संदर्भित किए गए, जिनमें से 56,356 मामलों का सफल निस्तारण किया गया। आपराधिक मामलों में 8,85,800 रुपये अर्थदंड वसूला गया। सक्सेशन मामलों में 68,88,898.41 रुपये के उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किए गए। बैंक प्री-लिटिगेशन मामलों में 4,13,94,529 रुपये की वसूली हुई, जबकि बिजली बिल बकाया मामलों में 89,50,000 रुपये की समझौता धनराशि तय की गई। प्रशासनिक व राजस्व से जुड़े 50,287 मामलों का निस्तारण करते हुए 12,56,932 रुपये अर्थदंड वसूला गया। लोक अदालत की विभिन्न पीठों द्वारा दीवानी, आपराधिक, वैवाहिक, मोटर दुर्घटना दावा, पॉक्सो एवं बैंक ऋण से संबंधित मामलों का व्यापक स्तर पर निस्तारण किया गया। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, अपर जिला जजगण, सिविल जजगण, न्यायिक मजिस्ट्रेट, अधिवक्ता, बैंक अधिकारी, न्यायालय कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में वादकारी उपस्थित रहे। लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जनपद न्यायाधीश द्वारा अपर जिला जज पुष्पा सिंह को नोडल अधिकारी नामित किया गया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं कर्मचारियों ने भी सराहनीय भूमिका निभाई।

रबी सीजन में उर्वरक वितरण पर सख्ती तीन दुकानदारों को नोटिस

ज्ञानपुर। रबी सीजन में गेहूं की टॉपड्रेसिंग को ध्यान में रखते हुए जिला कृषि अधिकारी कुमारी इरम ने जनपद भदोही में उर्वरक प्रतिष्ठानों एवं सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर तीन उर्वरक विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निरीक्षण में नागमलपुर सहकारी समिति पर रेट बोर्ड पर उर्वरक का मूल्य अंकित न होने, एग्री जंक्शन किसान सेवा केंद्र पर रजिस्टर में ग्राहकों के मोबाइल नंबर दर्ज न किए जाने तथा पाण्डेय खाद भंडार, पाली पर ओवररेटिंग की शिकायत की जांच किए जाने की पुष्टि हुई। इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। जिला कृषि अधिकारी कुमारी इरम ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनपद में यूरिया का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आने वाले सप्ताह में यूरिया उर्वरक की नई रैक भी लगने की संभावना है, जिससे किसानों को बिना किसी परेशानी के समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशासन की इस सख्ती से जहां उर्वरक वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, वहीं किसानों को राहत मिलने की उम्मीद भी बढ़ी है।

विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन 20 को, सनातन एकता का होगा प्रदर्शन

भदोही। जनपद भदोही के द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र स्थित श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट एवं संकल्प हिंदू समाज भदोही के संयुक्त तत्वावधान में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन 20 दिसंबर 2025, शनिवार को प्रातः 10 बजे से सायंकाल तक किया जाएगा। इस दिव्य एवं भव्य कार्यक्रम की जानकारी परम श्रद्धेय माता राजलक्ष्मी मंदा द्वारा दी गई। माता राजलक्ष्मी मंदा ने जनपद सहित आसपास के सभी सनातन धर्मावलंबियों से सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आवाहन किया है। उन्होंने बताया कि सम्मेलन का उद्देश्य सनातन धर्म को एक सूत्र में जोड़ना, सांस्कृतिक चेतना को जागृत करना तथा हिंदू समाज की एकता को सशक्त करना है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 180 फीट ऊँची भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग मूर्ति की स्थापना की जाएगी, जिससे यह स्थल धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यटक दृष्टि से विशेष पहचान प्राप्त करेगा। काशी और प्रयागराज के मध्य स्थित तपोवन स्थली, सीता समाहित स्थल भदोही के कटेबना सुंदरबन क्षेत्र को दिव्य धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का भी संकल्प लिया गया है। द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट एवं संकल्प हिंदू समाज भदोही की ओर से समस्त सनातन धर्म प्रेमियों, राष्ट्रभक्तों और श्रद्धालुओं का इस विराट हिंदू सम्मेलन में सादर आमंत्रण किया गया है, ताकि सभी मिलकर इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बना सकें।

सुरियावां में किशोर ने की आत्महत्या, परिजनों में कोहराम

सुरियावां। थाना क्षेत्र के ग्राम गोदमा में शुक्रवार को 17 वर्षीय किशोर गौरव चौहान द्वारा आत्महत्या किए जाने की घटना से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। गौरव, राम बहादुर चौहान का इकलौता पुत्र था और हाल ही में इंटरमीडिएट में प्रवेश लिया था। परिजनों के अनुसार गौरव पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहा था। शुक्रवार को वह अपने बड़े पिता स्व. बद्री नाथ चौहान के घर की चाबी लेकर वहां गया था। उस समय घर में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि परिवार के सदस्य रिश्तेदारी में गए हुए थे। देर रात घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। इससे पहले परिजनों ने शव को नीचे उतार लिया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता मुंबई में ड्राइवर का कार्य करते हैं और वर्तमान में बीमारी के चलते घर पर ही हैं। परिवार में माता मिता देवी तथा दो छोटी बहनें प्रिंसी और प्रिया हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है। घटना से गांव के लोग स्तब्ध हैं। थानाध्यक्ष राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि मृत्यु के कारणों का स्पष्ट खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा, पुलिस मामले की जांच कर रही है।

पूर्व सत्रों की विदेशी मदिरा के अवशेष स्टॉक का डीएम के निर्देश पर किया गया विनष्टीकरण

भदोही। आबकारी नीति 2025झ26 के प्रावधानों के तहत जिलाधिकारी शैलेष कुमार के आदेश पर गठित समिति की निगरानी में पूर्व सत्रों में निर्मित विदेशी मदिरा के अवशेष स्टॉक का विनष्टीकरण कराया गया। यह कार्रवाई 12 दिसंबर 2025 को गोपीगंज स्थित संदीप पैलेस, वार्ड संख्याझ15 के पीछे विदेशी मदिरा थोक अनुज्ञापन परिसर में सम्पन्न हुई। वर्ष 2024झ25 की बिक्री के बाद शेष तथा दिनांक 01 अप्रैल 2023 से पूर्व निर्मित विदेशी मदिरा के विभिन्न ब्रांड और धरिता की कुल 190 पेटी मदिरा का नियमानुसार निस्तारण किया गया। पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ समिति के समक्ष सम्पन्न कराई गई। विनष्टीकरण की कार्यवाही के

दौरान उप आबकारी आयुक्त (मीरजापुर प्रभार) श्रीराम पाण्डेय, जिला आबकारी अधिकारी अरुण कुमार शुक्ल एवं उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर मानसिंह उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई आबकारी नीति के अनुरूप की गई है, जिससे नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके और किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना समाप्त की जा सके।

पिकअप की टक्कर से ट्रक पलटा, चालक घायल

थरवई (प्रयागराज)। थरवई थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर शनिवार भोर करीब चार बजे बड़ा हादसा हो गया। भोपतपुर गांव के समीप तेज रफ्तार व अनियंत्रित पिकअप ने आगे चल रहे आलू लदे ट्रक में साइड मार दिया टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का एक पहिया टूटकर अलग हो गया और ट्रक वाहन अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई दुर्घटना में ट्रक चालक शिव मूरत यादव (45) पुत्र स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद यादव, निवासी किनपुरवा थाना नवाबगंज, जिला प्रतापगढ़ घायल हो गया। छिबरामऊ से गोपीगंज की ओर ट्रक में आलू लादकर ले जा रहा था। हादसे मेंट्रक चालक के सिर व शरीर में चोटें आईं। सूचना मिलते ही थरवई पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल चालक को पास के निजी अस्पताल में इलाज कराया गया हादसे के बाद पिकअप चालक वाहन सहित मौके से भाग निकला पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को सड़क से हटवाकर आवागमन शुरू कराया गया

गोरखपुर जं. स्टेशन यार्ड का निरीक्षण करते हुए महाप्रबंधक ,पूर्वोत्तर रेलवे श्री उदय बोरवणकर

गोरखपुर,ः पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री उदय बोरवणकर ने 13 दिसम्बर,2025 को वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ गोरखपुर जं. यार्ड में नये रूट रिले इंटरलॉकिंग पैनल का गहन निरीक्षण किया और वहॉ कार्यरत कर्मचारियों से सवारी एवं माल गाड़ियों के परिचालन पर विशेष चर्चा की। इसके उपरान्त महाप्रबंधक ने गोरखपुर जं. यार्ड का भी निरीक्षण किया, इस दौरान शंटिंग ऑपरेशन को संरक्षित तरीके से करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने गोरखपुर जं. स्टेशन के पश्चिमी छोर स्थित यार्ड में प्वांइट्स मशीनों की कार्यशीलता परखी। उन्होंने यार्ड को साफ-सुथरा रखने के साथ ही ड्रेनेज सिस्टम को भी साफ एवं दुरूस्त रखने लिए दिशा-निर्देश दिया। इस अवसर पर प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर तथा प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी श्री एम. एल. मकवाना, प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर श्री संजय सिंहल, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक एवं प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक श्री प्रकाश चन्द्र जायसवाल, मुख्य मालभाड़ा परिवहन प्रबंधक श्री श्री कृष्ण शुक्ल, महाप्रबंधक के सचिव श्री आनन्द ऋषि श्रीवास्तव एवं वरिष्ठ रेल अधिकारी उपस्थित थे।

अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता-2025 की विजेता टीम पूर्वोत्तर रेलवे को ट्रॉफी प्रदान करते हुए महाप्रबन्धक उदय बोरवणकर

गोरखपुर,ः रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे के तत्त्वावधान में सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम, गोरखपुर में 10 से 13 दिसम्बर, 2025 तक खेली गई 32वीं अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता-2025 के अंतिम दिन 13 दिसम्बर, 2025 को हुए फाइनल मुकाबले में पूर्वोत्तर रेलवे ने उत्तर रेलवे को 64-50 अंको से हराकर प्रतियोगिता जीत ली। पूर्वोत्तर रेलवे के भीम सिंह, राम आसरे यादव, दीपक कश्यप, सूर्यभान सिंह, विजय कुमार, अजय मल्ल के बेहतर प्रदर्शन के बदौलत पूर्वोत्तर रेलवे ने पूरे मैच के दौरान बढ़त बनाये रखा। उत्तर रेलवे प्रतियोगिता की उपजेता रही। उत्तर रेलवे के राजेश दहिया, सुनिल महला तथा राजेन्द्र का प्रदर्शन बेहतर रहा। तीसरे स्थान पर दक्षिण रेलवे रही। इस अवसर पर महाप्रबन्धक श्री उदय बोरवणकर ने विजेता एवं उपजेता टीमों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। इस अवसर पर महाप्रबन्धक श्री उदय बोरवणकर ने कहा कि मैं इस आयोजन के लिए सर्वप्रथम महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल, नई दिल्ली को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने 32वीं अखिल भारतीय, रेलवे सुरक्षा बल बास्केटबॉल प्रतियोगिता-2025 का आयोजन कराने का सुअवसर पूर्वोत्तर रेलवे को प्रदान किया। प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त श्री तारिक अहमद एवं उनकी टीम द्वारा इस प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। मुझे इस प्रतियोगिता के समापन समारोह में पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर रेलवे की बास्केटबॉल के खिलाड़ियों के कुशल प्रदर्शन देखने का अवसर प्राप्त हुआ। यह प्रतियोगिता सौहार्दपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई। इस प्रतियोगिता में सभी टीमों के खिलाड़ियों ने खेल भावना के साथ खेला। यह बहुत ही क्लोज और उत्साहपूर्ण मैच था, जिसमें पूर्वोत्तर रेलवे एवं उत्तर रेलवे की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल अब स्वयं रेल के एक यूनिट के रूप में अन्तर रेलवे प्रतियोगिताओं में भाग ले रही है, जिससे आपको अन्य राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिल रहा है। रेलवे सुरक्षा बल खेलों के साथ-साथ रेल यात्रियों के सुरक्षित यात्रा एवं रेल सम्पत्ति की बेहतर सुरक्षा हेतु वचनवद्ध है। इस अवसर पर प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेलवे सुरक्षा बल, पूर्वोत्तर रेलवे श्री तारिक अहमद ने सभी विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ रेल अधिकारियों एवं आयोजन समिति के पदाधिकारीगण, पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ासंघ के पदाधिकारियों, अधिकारियों एवं अन्य अतिथियों को स्वागत करते हुए प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों को बधाई दी और कहा कि इस प्रतियोगिता में पुरुषों की कुल आठ टीमों ने भाग लिया। टीमों को दो पूलों में बाँटकर कुल सोलह मैच खेले गये। प्रतियोगिता के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल टीम का चयन किया जाना है जो अन्तर रेलवे बास्केटबॉल प्रतियोगिता और अखिल भारतीय पुलिस खेलों में भाग लेंगी। उपमहानिरीक्षक सह वरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त/लखनऊ श्री चन्द्र मोहन मिश्र के कुशल निर्देशन में प्रतियोगिता का भव्य एवं कुशल आयोजन सम्पन्न किया गया, जिसके लिए वह एवं उनकी टीम बधाई के पात्र हैं। इस अवसर पर प्रमुख विभागाध्यक्ष, वरिष्ठ अधिकारी, क्षेत्रीय रेलों के सदस्यगण, बास्केटबॉल संघ गोरखपुर के सदस्यगण एवं पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के पदाधिकारी तथा भारी संख्या में बास्केटबॉल प्रेमी उपस्थित थे।

संक्षिप्त समाचार

नारी सुरक्षा/नारी सम्मान/नारी स्वावलंबन

पुलिस की सेवाओं व शासन द्वारा चलाये जा रहें विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा हैः

दिनांक 13.12. 2025 को मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 के

तहत पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही अभिमन्यु मांगलिक के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थानों की एंटी रोमियो/ महिला मिशन शक्ति टीमों द्वारा महिलाओं व बालिकाओं के बीच व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया।

जागरुक बनें, सुरक्षित रहें।

1090 - महिला पावर लाइन (महिलाओं के लिए हेल्पलाइन)

181 - महिला हेल्पलाइन (महिलाओं के लिए आपातकालीन सहायता)

112 - आपातकालीन सेवा (पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के लिए)

1076 - सीएम हेल्पलाइन (मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए शिकायतें और सुझाव)

1930 - साइबर सुरक्षा हेल्पलाइन (साइबर अपराधों के लिए सहायता)

छात्राओं को दी गई उपयोगी जानकारी

महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर

वूमेन पावर लाइन : 1090

पुलिस आपातकालीन सेवा : 112

महिला हेल्पलाइन : 181

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन : 1076

चाइल्ड लाइन : 1098

एम्बुलेंस सेवा : 108

स्वास्थ्य सेवा : 102

साइबर क्राइम हेल्पलाइन : 1930

2. प्रासंगिक विषयों पर मार्गदर्शन

गुड टच बैड टच की जानकारी।

घरेलू हिंसा व उससे संबंधित कानूनी प्रावधान।

साइबर अपराधों के खतरों और उनसे बचाव के उपाय।

शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ।

3. मिशन शक्ति केंद्रों की भूमिका

सभी को अवगत कराया गया कि जनपद के प्रत्येक थाने पर नवस्थापित मिशन शक्ति केंद्र कार्यरत हैं।

इन केंद्रों पर महिलाओं को त्वरित सहायता, परामर्श, शिकायत निस्तारण एवं योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।

पूर्वोत्तर रेलवे के इतिहास में पहली बार टीम चौंपियनशिप में स्वर्ण पदक एवं व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण एवं कांस्य पदक प्राप्त किया है।

गोरखपुर,ः अमरकंटक, मध्यप्रदेश में 13 दिसंबर,2025 को 56वीं अखिल भारतीय रेलवे क्रॉस कंट्री चौंपियनशिप में पूर्वोत्तर रेलवे की महिला टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता, पूर्वोत्तर रेलवे की ही महिला खिलाड़ी कुमारी नंदनी गुप्ता ने व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक प्राप्त किया है और कुमारी पूजा वर्मा ने व्यक्तिगत रूप से तीसरे स्थान पर आकर कांस्य पदक प्राप्त किया। पूर्वोत्तर रेलवे के इतिहास में पहली बार टीम चौंपियनशिप में स्वर्ण पदक एवं व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण एवं कांस्य पदक प्राप्त किया है। पूर्वोत्तर रेलवे की महिला खिलाड़ियों की इन उपलब्धियों पर महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे श्री उदय बोरवणकर, अध्यक्ष/नरसा श्री अभय कुमार गुप्ता, महासचिव/ नरसा श्री पंकज कुमार सिंह सहायक क्रीड़ा अधिकारी श्री चन्द्र विजय सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए, उन्हें बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

सफाई कर्मी को डीपीआरओ ने जारी किया कारण बताओ नोटिस

रामपुर/मिलकःअंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के जिला अध्यक्ष आदेश शंखधार ने ग्राम पंचायत गदईया निकट हरसुनगला में तैनात सफाई कर्मी महेन्द्र पाल उर्फ. पप्पू की शिकायत खण्ड विकास अधिकारी मिलक से की थी।जिसमें आरोप लगाया था कि सफाई कर्मी वर्ष 2016 में कुल 09 दिनों तक जेल में रहा है,उसकी कोई भी जानकारी विभाग को नहीं दी गई और माह अक्टूबर 2016 का पूरा वेतन विभाग से लिया तथा वर्तमान समय में तैनाती ग्राम पंचायत गदईया निकट हरसुनगला में है वहां सफाई करने स्वयं न जाकर एक प्राईवेट कर्मचारी को सात हजार रुपए प्रति माह के हिसाब से नियुक्त कर रखा है।खुलेआम सरकारी नियमों की अनदेखी की जा रही है।इसी सम्बन्ध में जिला पंचायत राज अधिकारी ने सफाई कर्मी को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिनों में जवाब देने को कहा है।अब देखना यह होगा कि सफाई कर्मी क्या जवाब देगा।

ग्रामीण व शहरी युवाओं के लिए विधायक खेल स्पर्धा का आयोजन

रामपुरःजिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास अधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में जनपद की समस्त विधानसभाओं में ह्लमाङ्क विधायक खेल स्पर्धाह्व का आयोजन किया जा रहा है।इस खेल आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ते हुए उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि विधानसभा 36 बिलासपुर में दिनांक 15 एवं 16 दिसम्बर,2025 को सर्वसंस्कृति स्कूल,बिलासपुर में,विधानसभा 38 मिलक में 16 एवं 17 दिसम्बर,2025 को मिनी स्टेडियम,तिराहा (मिलक) में,विधानसभा 37 नगर रामपुर में दिनांक 17 एवं 18 दिसम्बर,2025 को शहीदे आजम स्टेडियम,बमनपुरी (रामपुर) में,विधानसभा 35 चमरौआ में 18 एवं 19 दिसम्बर,2025 को शहीदे आजम स्टेडियम,बमनपुरी (रामपुर) में तथा विधानसभा 34 स्वार में 26 एवं 27 दिसम्बर,2025 को मंसब अली स्टेडियम,टांडा में प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएँगी।

गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा ने गिल का किया बचाव, बोले- सिर्फ दो मैच से आकलन करना गलत होगा

नई दिल्ली : भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल टी20 में अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। हालांकि, गुजरात टाइंटस के मुख्य कोच आशीष नेहरा इससे चिंतित नहीं है और उन्होंने अपने कप्तान का समर्थन किया है। आईपीएल की फ्रेंचाइजी गुजरात टाइटंस के मुख्य कोच आशीष नेहरा टीम के कप्तान शुभमन गिल के मौजूदा फॉर्म से चिंतित नहीं है। नेहरा का मानना है कि अगर गिल का आकलना दो मैच से करेंगे तो यह उनके साथ गलत होगा। गिल फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में ले रहे हैं। चोट के बाद वापसी करते हुए गिल का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और शुरूआती दो मैचों में वह बल्ले से दम नहीं दिखा सके हैं। टी20 में अच्छा नहीं रहा है गिल का प्रदर्शन गिल ने टी20 अंतरराष्ट्रीय में पिछले 10 मुकाबलों में 181 रन बनाए हैं और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 140 से भी कम का रहा है। नेहरा पिछले दो आईपीएल सीजन से गिल को नजदीक से देख रहे हैं।

कफ सिरप तस्करी, ईडी का बड़ा एक्शन

एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही समेत 25 के ठिकानों पर छापा

लखनऊः कोडीनयुक्त कफ सिरप के तस्करों के 25 ठिकानों पर एऊ की रेड दूसरे दिन भी जारी है। इस नशीले कफ सिरप का 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रैकेट है। जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई शुक्रवार सुबह शुरू हुई कार्रवाई शनिवार को भी जारी है। 67 आरोपियों के खिलाफ दर्ज ECIR (प्रवर्तन मामले की रिपोर्ट) के 9 दिन बाद की गई इस तलाशी में एजेंसी को कई महत्वपूर्ण वित्तीय और डिजिटल सुराग मिले हैं, जिनसे रैकेट की बड़े लेवल का नेटवर्क और ज्यादा साफ होता जा रहा है। एऊ अब इस नेटवर्क के फाइनेंशियल ब्रेन और राज्य-दर-राज्य चल रहे सप्लाई चेन की नई परतें खोलने में जुटी है।

एऊ की कार्रवाई से मिले कई अहम दस्तावेज

यूपी, झारखंड और गुजरात के 25 ठिकानों पर एक साथ सर्च ऑपरेशन के बाद एऊ के हाथ बड़े दस्तावेज और डिजिटल डेटा लगे

हैं। इनमें कथित पेमेंट एंट्री, फर्जी बिलिंग, इंटर-स्टेट ट्रांसपोर्ट परमिट और कई कंपनियों के संदिग्ध लेन-देन शामिल हैं। एक हजार करोड़ का बीते पांच का नेटवर्क मिला है। जांच से यह स्पष्ट हो रहा है कि कफ सिरप की तस्करी केवल मेडिकल डायवर्जन तक सीमित नहीं थी, बल्कि फर्जी कंपनियों के जरिए अलग-अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर माल भेजा जा रहा था। 3 से ज्यादा राज्यों में भी फैल सकती है जांच एऊ के सूत्रों के अनुसार, शुरूआती तलाशी में मिले इनपुट्स से यह साफ है कि नेटवर्क की जड़ें देश के कई हिस्सों में फैली थीं। जिन कंपनियों और व्यक्तियों के नाम सामने आए हैं, वे न सिर्फ यूपी और झारखंड में बल्कि गुजरात के औद्योगिक क्षेत्रों में भी सक्रिय थे। अहमदाबाद और सूरत में मिले दस्तावेज बताते हैं कि कफ सिरप को फर्जी फार्मा सप्लाई के नाम पर बाहर भेजा जा रहा था। जांच एजेंसी अब इस मैपिंग को और विस्तार दे रही है। जिन ठिकानों पर छापे पड़े हैं, वहां से मिले दस्तावेज और एक्सेल शीट्स में कई ऐसे नाम और फर्मों का उल्लेख मिला है, जो अभी तक किसी भी एफआईआर या पुलिस रिकॉर्ड में शामिल नहीं थे। कफ सिरप की बिक्री को बिल से वैध दिखाते थे एऊ ने इन नए संदिग्धों का बैकग्राउंड स्कैन करना शुरू कर दिया है और जल्द ही उन्हें भी जांच के दायरे में लाया जा सकता है। जांच में यह सामने आया है कि रैकेट फर्जी बिलिंग और हवाला नेटवर्क के सहारे कफ सिरप की अवैध बिक्री से हुई कमाई को वैध दिखाता था। कई कंपनियां सिर्फ कागज पर बनाई गई थीं, जिनके नाम पर इंटरस्टेट ई-वे बिल जेनरेट होते थे। एऊ इन कंपनियों के सभी बैंक खातों और उनके माध्यम से हुई करोड़ों की लेन-देन की फॉरेंसिक ऑडिट करा रही है।

चौधरी गये तो चौधरी ही आयेंगे भी

लखनऊ,। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष फाइनल कर दिया। भूपेन्द्र चौधरी हटेंगे और पंकज चौधरी आयेंगे। चौधरी गये और चौधरी आ रहे हैं फर्क सिर्फ यह है कि भूपेन्द्र चौधरी जाट हैं और पंकज चौधरी कुर्मी। भूपेन्द्र चौधरी को उत्तर प्रदेश बीजेपी का सेनापति तब बनाया गया था जब जाट किसान आंदोलन को लेकर नाराज चल रहे थे। जाट वोटर को खुुश करने के लिए भूपेन्द्र चौधरी को प्रेसीडेंट बनाकर लाया गया था।इस बार कुर्मी वोटर को खुुश करने के लिये पंकज चौधरी को प्रेसीडेंट की कमान दी जा रही है। 2024 के लोक सभा चुनाव में कुर्मी वोटर अखिलेश यादव के साथ चले गये और सात कुर्मी सांसद जीत गये। भारतीय जनता पार्टी को कुर्मी वोटरों ने लोक सभा में बड़ा झटका दिया। 2027 के विधान सभा चुनाव में कुर्मी वोट को अपनी तरफ खींचने का बड़ा दाँव हैं पंकज चौधरी। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि सात बार के सांसद पंकज चौधरी के सेनापति बनने से कुर्मी भागकर भाजपा के साथ वापस आ जायेगा। वैसे कुर्मी 2022 के विधान सभा चुनाव से ही सपा की तरफ खिसक गया था लेकिन 24 में पूरी तरह से वह सपा में चला गया। भारतीय जनता पार्टी पंकज चौधरी के जरिये कुर्मी वोटर अपनी तरफ खींच सकती है। पंकज चौधरी बड़े कुर्मी नेता हैं और अपनी बिरादरी में उनकी काफी पैठ है। सौम्य और सरल हैं यह भाजपा खैर फायदेमंद हो सकता है।पंकज चौधरी कल सुबह की फ्लाईट से लखनऊ पहुँच गये हैं।उनका एयरपोर्ट पर बहुत ही गर्मजोशी के साथ बीजेपी के कार्यकताओं ने स्वागत किया है। पंकज चौधरी ने खुद खुशी का इजहार करते हुए पार्टी कार्यकताओं और शुभचिंतको का शुक्रिया अदा किया है। उनका नामांकन फार्म आज दाखिल हो गया है। अब करीब करीब उनका बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनना तय हो गया है।घोषणा होने की सिर्फ औपचारिकता बाकी है।

पेंशन पुनरीक्षण व अन्य लाभ का उल्लेख ना होने पर जताई नाराजगी

लखनऊ,। उ.प्र.स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ द्वारा केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुति पर आठवें वेतन आयोग जो जनवरी 2026 से दिये जाने का जारी नोटीफिकेशन में पेंशन धारको की पेंशन पुनरीक्षण व अन्य मिलने वाले लाभो का समावेश न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मा.प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री भारत सरकार सहित सचिव वित्त भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री उ.प्र.आदि को पत्र प्रेषित कर समय रहते यह तीनो प्रस्ताव को हटाते हुए पूर्व की भातिं पेंशन धारको को यह लाभ दिये जाने की मांग की है। उ.प्र.स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शशिकुमार मिश्र ने कहा कि प्रदेश के लाखों-लाख पेंशन धारक कर्मचारी चाहे वह स्थानीय निकाय, राज्य,निगम व शिक्षक हो को पेंशन पुनरीक्षण व अन्य मिलने वाले पेंशनर लाभ जो जनवरी 2026 से दिया जाने वाले आठवें वेतन आयोग के जारी नोटीफिकेशन में केन्द्रीय वेतन आयोग के द्वारा आठवें वेतन आयोग के गठन हेतु जारी नोटीफिकेशन में इस बार पेंशन धारक कर्मचारियो हेतु पेंशन पुनरीक्षण एवं अन्य पेशंनर लाभो का कोई प्रस्ताव नही दिया गया। जिसका विरोध करते हुए वह तीनो प्रस्ताव जो पेंशन धारको के लिए हित कर नही है,तत्काल हटाने हेतु प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री भारत सरकार व सचिव वित्त भारत सरकार के साथ साथ मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश आदि को पत्र प्रेषित कर समय रहते आठवें वेतन आयोग की संस्तुतियो में पूर्व की भांति पेंशन धारको की पेंशन पुनरीक्षण व अन्य मिलने वाले पेंशन लाभो का ध्यान देते हुए उन्हे दिये जाने के आदेश जारी किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें हजारों पेंशनर्स के साथ न्याय नही किया गया है।

महासमिति ने एसआईआर कर रही टीम का उत्साह बढ़ाया

लखनऊ,। इंदिरा नगर आवासी महासमिति के महासचिव सुशील कुमार बच्चा ने बताया कि आर एल बी सेक्टर 14 इंदिरानगर तथा राजकीय बालिका विद्यालय सेक्टर 11 इंदिरा नगर लखनऊ 173 पूर्व के बूथ संख्या -89 से 100 तक बी एल ओ द्वारा शत-प्रतिशत एस आई आर फॉर्म भरवाने में मदद करने के लिए टीम के पर्यवेक्षक विनोद कुमार की देखरेख में हुआ पूरी टीम का उत्साह वर्धन किया गया और उनका फूल और मालाओं से स्वागत किया गया। महासमिति द्वारा जनता से अपेक्षा की गई है कि कोई मतदाता छूटने ना पाएं। टीम ने लगन से काम करने का भरोसा भी दिलाया। सुशील बच्चा ने कहा कि महासमिति अन्य बूथों पर बी एल ओ को सम्मानित करने का काम करेगी।इस मौके पर महासमिति के अध्यक्ष देवी शरण त्रिपाठी एवं संयुक्त सचिव सविता शुक्ला भी मौजूद रही। सम्मानित बी एल ओ मे दिवाकर पटेल ,विभूति श्रीवास्तव, प्रियंका वर्मा, शरद सोनी, प्रीति दुबे , पंकज कुमार, अनूप कुमार, रंजीत कुमार ,गौतम शिवधनी, मोहम्मद रियाज, शिव वरन राम, बिहारी लाल श्रीवास्तव रहे।

अकबर ने मांगा लाल किला और कुतुब मीनार

लखनऊ,। अलीगढ़ जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसने प्रशासन से लेकर पुलिस तक को चौंका दिया है। अलीगढ़ महानगर के बन्ना देवी इलाके में रहने वाले एक प्लंबर ने प्रधानमंत्री कार्यालय के आईजीआरएस पोर्टल पर पत्र भेजकर खुद को देश की ऐतिहासिक धरोहरों दिल्ली और आगरा के लाल किले तथा कुतुब मीनार का मालिक और वारिस बताया है।उसने इन धरोहरों को खाली कराकर अपने सुपुर्द करने या फिर प्रधानमंत्री से मुलाकात कराने की मांग की है।बन्ना देवी निवासी अकबर नामक व्यक्ति ने सितंबर और नवंबर माह में आईजीआरएस पोर्टल पर दो हाथ से लिखे पत्र भेजे। इन पत्रों में उसने दावा किया कि दिल्ली और आगरा के लाल किले तथा कुतुब मीनार उसकी संपत्ति हैं। पत्र में लिखा गया कि या तो इन ऐतिहासिक इमारतों को खाली कराकर उसे सौंप दिया जाए या फिर वह जितनी धनराशि मांगे, उतनी उसे प्रदान की जाए। उसने प्रधानमंत्री से सीधे मुलाकात कराने की मांग रखी। अकबर ने अपने एक पत्र में खुद की जान को खतरा होने की बात भी लिखी है। उसने दावा किया कि देश के अलग-अलग राज्यों के 10 से अधिक बड़े विपक्षी नेताओं से उसे जान का खतरा है। पत्र में जिन नेताओं के नामों का उल्लेख किया गया है, वे सभी देश की राजनीति में जाने-पहचाने चेहरे बताए जा रहे हैं।पीएमओ को मिले इन पत्रों को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए अलीगढ़ पुलिस को भेजा गया। बन्ना देवी थाना पुलिस ने मामले का सत्यापन शुरू की। पुलिस महकमे में भी हलचल मच गई, क्योंकि मामला सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय और देश की ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़ा हुआ था।मामले की जांच सीओ द्वितीय कमलेश कुमार को सौंपी गई। पुलिस ने पत्र भेजने वाले अकबर को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू की।

योगी सरकार का किसानों की आर्थिक समृद्धि पर जोर

लखनऊ,। योगी सरकार का अन्नदाता किसानों की आर्थिक समृद्धि पर विशेष जोर है। योगी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बिक्री के लिए 4645 क्रय केंद्र स्थापित कर सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, वहीं डीबीटी के माध्यम से किसानों को सीधे अकाउंट में पैसे भी भेज रही है। 3.15 लाख से अधिक किसानों से 19.14 लाख मीट्रिक टन धान खरीद हो चुकी है। इसके एवज में किसानों को 4500 करोड़ से अधिक का भुगतान भी किया जा चुका है। बाजरा बिक्री करने वाले 35 हजार से अधिक किसानों को 421.39 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में श्रीअन्न की खरीद पहली अक्टूबर से हो रही है। पहली अक्टूबर से पश्चिम उत्तर प्रदेश व पहली नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान खरीद हो रही है।योगी सरकार साल दर साल अपने ही रिकॉर्ड तोड़ रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 13 दिसंबर तक 6.70 लाख किसानों ने धान बिक्री के लिए पंजीकरण कराया था, जबकि 2025-26 में अब तक यह आंकड़ा 7.83 लाख से अधिक है। बाजरा बिक्री के लिए पिछले वर्ष इस अवधि तक 21630 किसानों का पंजीकरण हुआ था, जो इस वर्ष में 80 हजार से अधिक हो गया है। वहीं ज्वार व मक्का में भी पंजीकरण बढ़ गया। ज्वार बिक्री के लिए पिछले साल 12 हजार किसानों ने पंजीकरण कराया था, इस साल 16 हजार से अधिक किसानों का पंजीकरण हो चुका है। बाजरा खरीद 33 व ज्वार खरीद 11 जनपदों में हो रही है।खाद्य व रसद विभाग के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धान की बिक्री, किसानों को भुगतान, क्रय केंद्र की व्यवस्था आदि को लेकर निरंतर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को समय से भुगतान करने का निर्देश दिया है। शनिवार दोपहर 12 बजे तक 3.15 लाख किसानों से 19.14 लाख मीट्रिक टन धान खरीद हो चुकी है। इस एवज में यूपी के किसानों को 4541.94 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। 4645 क्रय केंद्र भी स्थापित हो चुके हैं। वहीं श्रीअन्न की बात करें तो बाजरा किसानों को 421.39 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, पिछले वर्ष इस अवधि तक 187.98 करोड़ रुपये भुगतान हुआ था। सीएम योगी की मॉनीटरिंग से इस वर्ष किसानों को तेजी से भुगतान किया जा रहा है। ह्यश्रीअन्नह्न की खरीद पहली अक्टूबर से शुरू हुई थी, जो 31 दिसंबर तक चलेगी। श्रीअन्न के अंतर्गत बाजरा 33, मक्का 25 व ज्वार खरीद 11 जनपदों में हो रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी व पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी तक धान खरीद होगी। धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 व ग्रेड ए का 2389 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। ज्वार का न्यूनतम समर्थन मूल्य मालदांडी 3749, ज्वार हाईब्रिड 3699 रुपये प्रति कुंतल, बाजरा का 2775 व मक्का का 2400 रुपये प्रति कुंतल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

फॉर्च्यूनर ने कोर्ट मुंशी को टक्कर मारी-50 फीट दूर गिरा

लखनऊः लखनऊ में सड़क किनारे चाय पी रहे कोर्ट मुंशी को तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने टक्कर मार दी, जिससे वह उछलकर 50 फीट दूर जा गिरे। इसके बाद ड्राइवर ने भागने के चक्कर में उनके पेट पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। लोगों ने दौड़ाकर गाड़ी को रुकवाया, लेकिन ड्राइवर मौका पाकर फरार हो गया। पुलिस ने फॉर्च्यूनर को कब्जे में लिया है। गाड़ी पर बीजेपी का झंडा और विधानसभा का पास लगा है। घटना गोमती नगर के विभूति खंड इलाके में शनिवार सुबह हुई। मृतक की पहचान गंगापुरवा गांव के (सीतापुर) के रहने वाले सुनील कुमार (32) के रूप में हुई। बताया गया कि सुनील हाईकोर्ट में मुंशी थे। लखनऊ में सुषमा हॉस्पिटल के पास किराए का मकान लेकर रहते थे। सुबह चाय पीने घर से निकले सुनील शनिवार सुबह करीब 6 बजे चाय पीने सुषमा हॉस्पिटल के पास गए थे। सड़क किनारे खड़े होकर चाय पी रहे थे तभी फैजाबाद रोड की तरफ से आई तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सुनील उछलकर 50 फीट दूर जाकर गिरे। भगाने के चक्कर में फॉर्च्यूनर चालक ने गाड़ी उनके पेट के ऊपर चढ़ा दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वह मौजूद लोगों ने गाड़ी रुकवा ली, लेकिन चालक फरार हो गया। पुलिस आरोपी की पहचान में लगी है।

युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में योगी सरकार की पहल

लखनऊ,। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल द्वारा प्रदेश के सभी कौशल विकास केंद्रों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अधिकारियों द्वारा विभिन्न जनपदों में प्रशिक्षण केंद्रों का क्षेत्रीय भ्रमण कर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति, गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है।मंत्री के निर्देशों के अनुपालन में अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह ने उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण केंद्रों, सिद्धार्थनगर एवं बलरामपुर का क्षेत्रीय भ्रमण किया । इस दौरान मिशन की टीम उपस्थित रही। भ्रमण का उद्देश्य केंद्रों पर संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा, नए बैचों की प्रारंभिक स्थिति का आकलन तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुनिश्चित करना था। निरीक्षण के दौरान अपर मिशन निदेशक ने प्रशिक्षार्थियों से संवाद कर उनके प्रशिक्षण अनुभवों की जानकारी ली, फीडबैक प्राप्त किया तथा उन्हें रोजगार के उपलब्ध अवसरों, भविष्य की करियर संभावनाओं एवं मिशन की आगामी प्रशिक्षण योजनाओं के संबंध में विस्तार से अवगत कराया। ट्रेनिंग पार्टनर्स, सेंटर मैनेजर एवं एमआईएस मैनेजर्स को आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए गए। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के सहायक निदेशक आशीष कुमार द्वारा प्रशिक्षण केंद्रों, बहराइच एवं श्रावस्ती का क्षेत्रीय भ्रमण किया गया। उनके साथ संबंधित मिशन टीम उपस्थित रही। प्रशिक्षण केंद्रों में स्थापित लैब, उपकरणों एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया गया। सहायक निदेशक ने प्रशिक्षार्थियों से प्रत्यक्ष संवाद कर प्रशिक्षण की गुणवत्ता, सीखने की प्रक्रिया एवं प्राप्त फीडबैक की जानकारी ली तथा उन्हें रोजगार, करियर संभावनाओं एवं आगामी प्रशिक्षण योजनाओं से अवगत कराया।अपर मिशन निदेशक प्रिया सिंह ने कहा कि युवाओं को सशक्त बनाना, उनके कौशल को सुदृढ़ करना तथा उन्हें रोजगार से जोड़ना उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन का प्रमुख उद्देश्य है। सहायक निदेशक आशीष कुमार ने सबको हुनर, सबको काम के ध्येय को दोहराते हुए कहा कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करना सभी ट्रेनिंग पार्टनर्स की जिम्मेदारी है ताकि युवाओं को बिना किसी बाधा के गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

विघुत बिल संशोधन और निजीकरण के खिलाफ आज दिल्ली में बनेगी रणनीति

लखनऊ। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध के साथ इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में बिजली कर्मचारियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों के केन्द्रीय पदाधिकारियों के साथ 14 दिसंबर को दिल्ली में मीटिंग हो रही है जिसमें संयुक्त संघर्ष की रणनीति तय की जाएगी और आंदोलन के कार्यक्रमों की घोषणा की जायेगी। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी आफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज एंड इंजीनियर्स की ओर से इस मीटिंग में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया पावर डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन (एटक), इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीटू), इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन (इंटक), ऑल इंडिया पावर मेन्स फेडरेशन (ए आई यू टी यू सी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री सम्मिलित होंगे। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन और विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के संयोजक शैलेंद्र दुबे इस महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल होंगे। उन्होंने आज यहां बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियनों की इस बात पर सहमति हो गई है कि इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 संपूर्ण बिजली क्षेत्र का निजीकरण करने के लिए लाया गया है जो किसानों और आम उपभोक्ताओं के लिए घातक है अतरू इसका राष्ट्रव्यापी विरोध किया जाना बहुत जरूरी है।विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय पदाधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी और इंजीनियर एक साल से अधिक से पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में लगातार संघर्ष कर रहे हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं।इसी बीच भारत सरकार ने पूरे देश के ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसके अतिरिक्त ग्रुप आफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्यों पर यह दबाव डाला जा रहा है कि केंद्र सरकार तभी वित्तीय सहायता करेगी जब राज्य निजीकरण के तीन विकल्पों में से एक विकल्प को स्वीकार करें।उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों की निजीकरण की इन कोशिशें को देखते हुए बिजली के निजीकरण के विरोध में सारे देश के बिजली कर्मचारियों के साथ किसान और मजदूर संगठन भी आ गए हैं और राष्ट्रव्यापी आंदोलन की रूपरेखा 14 दिसंबर को तय की जाएगी।

लखनऊ सिविल डिफेंस के 90 और स्वयंसेवक हुए प्रशिक्षित

लखनऊः सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक किसी भी आपदा से निपटने

में सक्षम है। ये बात लखनऊ सिटी मजिस्ट्रेट ज्ञान चंद्र गुप्ता ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन के अवसर पर प्रशिक्षार्थियों के समक्ष तारीफ करते हुए कही। स्वयंसेवक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के अवसर पर लखनऊ सिविल डिफेंस के उपनियंत्रक रविन्द्र कुमार व चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा ने मुख्य अतिथि ज्ञान चंद्र गुप्ता, सिटी मजिस्ट्रेट लखनऊ का बुके देकर स्वागत किया। तत्पश्चात कार्यालय नागरिक सुरक्षा लखनऊ की तरफ से स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। गौरतलब है कि इन दिनों गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मून हॉल में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित स्वयंसेवक क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम योजित किया जा रहा है। जिसमें 90-90 स्वयंसेवकों के सात सात दिन के कुल 4 बैच आयोजित होंगे, इस प्रकार पूरे लखनऊ सिविल डिफेंस से कुल 360 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किए जाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा दिया गया है। लखनऊ सिविल डिफेंस के अधिकारी सीनियर असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर मनोज वर्मा ने बताया कि अपर जिलाधिकारी पूर्वी महेंद्र पाल सिंह के दिशा निर्देशन में सुचारू रूप से अब तक दो बैच चलाए जा चुके हैं, जिसमें 180 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। तीसरा बैच आगामी सोमवार 15 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 22 दिसंबर को समाप्त होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में सीनियर असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर मनोज वर्मा, ऋषि कुमार, ममता रानी, रेखा पांडेय, मुकेश कुमार, स्टाफ अफसर ऋतुराज रस्तोगी, नफीस अहमद, ऐश्वर्य, मनोज कुमार वर्मा, कमलेश शुक्ला, नफीस, पंकज पंत, अम्बेश दुबे, अजय, समीक्षा, फैसल, फरीद ने विशेष सहयोग प्रदान किया।

बिना मर्जी बदल डाले 33 लाख से अधिक मीटर

बिना उपभोक्ता सहमति स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में बदलना गलत

लखनऊ,। देश में स्मार्ट मीटरों की स्थापना और उनके प्रभाव को लेकर 11 दिसंबर 2025 को लोकसभा में पूछे गए एक सवाल पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा दिया गया वक्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो लंबे समय से पोस्टपेड वह प्रीपेड के विकल्प को स्पष्ट कर दिया है अपने उत्तर में उन्होंने स्पष्ट किया है कि पोस्टपेड सेवा पारंपरिक रूप से डिफॉल्ट मोड रही है, और जो लागू है। जबकि स्मार्ट प्रीपेड मीटरों की स्थापना आरडीएसएस योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर सरकारी प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं उच्च लोड उपभोक्ताओं के लिए की जा रही है। आगे चलकर, जब इसके लाभ स्पष्ट होंगे, तभी अन्य उपभोक्ताओं के लिए इस पर विचार किया जाएगा। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर गरीब व छोटे घरेलू उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटरों को बिना उनकी सहमति के पोस्टपेड से प्रीपेड मोड में बदला जा रहा है। प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में अब तक लगभग 53 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 33 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के मीटर बिना सहमति के प्रीपेड मोड में कन्वर्ट कर दिए गए हैं। यह पूरी तरह से मनमानी और कानून के विरुद्ध है। अवधेश वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद लगातार यह मुद्दा उठाता रहा है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) के अंतर्गत उपभोक्ताओं को पोस्टपेड या प्रीपेड मीटर चुनने का स्पष्ट विकल्प दिया गया है। यह एक राष्ट्रीय कानून है और इसका उल्लंघन किसी भी स्तर पर स्वीकार्य नहीं है।उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि जब स्वयं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने लोकसभा में यह स्वीकार कर लिया है कि पोस्टपेड सेवा डिफॉल्ट मोड है और प्रीपेड मीटरों का विस्तार चरणबद्ध तरीके से किया जाना है, तो फिर प्रदेश में पावर कॉरपोरेशन उपभोक्ताओं के विकल्प को क्यों समाप्त कर रहा है। यह न केवल उपभोक्ताओं के अधिकारों पर कुठाराघात है, बल्कि विद्युत अधिनियम 2003 का खुला उल्लंघन भी है।उन्होंने कहा कि अभी भी समय है कि पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन भारत के कानून का सम्मान करे और किसी भी उपभोक्ता के स्मार्ट मीटर को बिना उसकी लिखित सहमति के प्रीपेड मोड में कन्वर्ट न किया जाए। उपभोक्ताओं को उनका वैधानिक विकल्प हर हाल में दिया जाना चाहिए।श्री वर्मा ने चेतावनी दी कि यदि पावर कॉरपोरेशन उच्च प्रबंधन ने अपनी कार्यप्रणाली में तत्काल सुधार नहीं किया और उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन जारी रखा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद इस मामले को केंद्रीय स्तर पर उठाएगी और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की जाएगी।

मंत्र भारत

लखनऊ-रविवार,14 दिसम्बर 2025

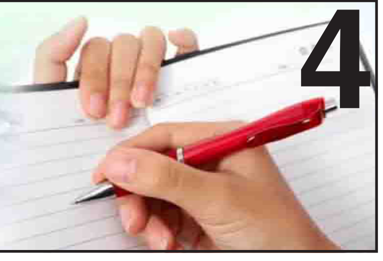

संपादकीय

पीड़ा से मुक्ति

देश में लंबे समय से यह मुद्दा सार्वजनिक विमर्श में रहा है कि विषम परिस्थितियों में एक त्रासदी से मुक्ति हेतु इच्छामृत्यु की अनुमति दी जाए या नहीं। समय-समय पर अदालती फैसलों ने मार्गदर्शक भूमिका निभाई है। साथ ही कोशिश की गई है कि इस छूट का दुरुपयोग न किया जा सके। हाल ही में एक ज्वलंत प्रसंग पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट टिप्पणी थी कि हमें अब कुछ करना होगा, इस तरह के त्रासद जीवन की कोई तार्किकता नहीं है। दरअसल, यह मामला एक 32 वर्षीय युवक का है, जो पिछले 13 सालों से कोमा जैसी स्थिति में है। यह अब केवल महज चिकित्सीय त्रासदी का मामला नहीं रह गया है। अब यह एक महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक प्रश्न भी बन चुका है। निश्चित रूप से शीर्ष अदालत की टिप्पणी देश में जीवन के अंतिम क्षणों में गरिमापूर्ण व्यवहार के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। निश्चय ही यह प्रसंग अतीत में बहुचर्चित अरुणा शानबाग के मामले की यादें फिर से ताजा कर देता है। इस प्रसंग ने ही देश को पहली बार निष्क्रिय इच्छामृत्यु के प्रश्न का सामना करने के लिये बाध्य किया था। वर्ष 2011 में, सुप्रीम कोर्ट ने अरुणा शानबाग के मामले में फैसला सुनाते हुए, सैद्धांतिक रूप से निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी थी। दरअसल, अरुणा शानबाग एक भयानक हमले के बाद से ही 42 वर्षों से कोमा जैसी स्थिति में रही थीं। भले ही अदालत ने इस मामले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, लेकिन साथ ही उसके साथ कुछ प्रतिबंधात्मक सुरक्षा उपायों के अनुपालन के भी निर्देश दिए थे। निश्चित रूप से इस मामले में अदालती फैसला नैतिक प्रेरणा का स्रोत भी बना। कालांतर में जिसके चलते वर्ष 2018 में एक संविधान पीठ ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की। साथ ही इसके लिये एक आवश्यक प्रक्रिया भी निर्धारित की थी। जिसका मकसद था कि समाज में कहीं इस छूट का दुरुपयोग आपराधिक स्वार्थों के लिये न किया जा सके। वर्ष 2023 में, अदालत ने इन दिशानिर्देशों को और सरल बनाने का प्रयास किया। जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि प्राथमिक और माध्यमिक चिकित्सा बोर्डों द्वारा स्थिति के मूल्यांकन की आवश्यकता रहेगी। फिलहाल देश में वही प्रक्रिया आज भी चल रही है। बहरहाल, वर्तमान मामले में बार-बार की गई अपीलें, इससे जुड़ी खामियों को भी उजागर करती हैं। दरअसल, ऐसे मामलों में पीड़ित को घर में दी जाने वाली देखभाल अपर्याप्त ही साबित होती है। वहीं दूसरी ओर राज्य का समर्थन भी पर्याप्त नहीं रहा है। इसके अलावा ऐसे मामलों से जुड़ी अनसुलझी नैतिक दुविधाएं असमंजस की स्थिति पैदा करती रही हैं। निस्संदेह, इस मामले में किसी युवा वयस्क के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु की पहली स्पष्ट स्वीकृति हो सकती है। आज देश में हजारों मरीज कोमा जैसी अवस्था में नारकीय जीवन जी रहे हैं। जो उनके परिवारों के लिये भी एक त्रासदी की स्थिति है। जहां परिवार एक ओर भावनात्मक संकट से जूझ रहे होते हैं, वहीं रोगी के उपचार से जनित आर्थिक बोझ भी निरंतर बढ़ता जाता है। दूसरी ओर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार पर भी सवाल उठते रहे हैं। निस्संदेह, अदालत को जटिल परिस्थितियों में जैविक अस्तित्व के कठोर विस्तार के बजाय रोगी की मुक्ति और परिवार की पीड़ा को प्राथमिकता देनी चाहिए। ऐसे में यदि एम्स 17 दिसंबर तक मामले में जीवन की निरर्थकता की पुष्टि करता है, तो निष्क्रिय इच्छामृत्यु की स्वीकृति एक मिसाल कायम कर सकती है। इसके बाद दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा उपायों को भी स्पष्ट किया जा सकेगा। साथ ही जीवन के अंतिम विकल्पों का सम्मान किया जा सकेगा। देश के नीति-नियंताओं को कोमा जैसी अवस्था में सालों जूझते लोगों के मामले में स्पष्ट दिशा-निर्देश बनाने चाहिए, जिससे ऐसे रोगियों की उपचारात्मक देखभाल और परामर्श को एकीकृत किया जा सके। मानवीय करुणा की मांग है कि जीवन की पवित्रता और पीड़ा की क्रूरता के बीच संतुलन बनाया जाए। इच्छामृत्यु जब सहमति से होगी तो मानवता को कायम रखा जा सकता है। न्यायपालिका को ऐसा न्याय देना चाहिए, जो रोगी को पीड़ा से मुक्त करे और एक करुणामय भविष्य का मार्ग प्रशस्त करे।

हमारे हितों की अनदेखी कर हमसे दोस्ती मुमकिन नहीं

क्रांति से शांति तक नामक फोटो प्रदर्शनी नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय कार्यालय, सानेपा, ललितपुर में आयोजित किया गया था, जहां वर्तमान प्रधानमंत्री प्रचंड आये, और इसके प्रकारांतर पीएम इन वेटिंग, केपी शर्मा ओली भी पधारे। उस अवसर पर प्रचंड का नेपाली कांग्रेस के नेता शेर बहादुर देउबा से क्या संवाद हुआ, वह सार्वजनिक नहीं हुआ है। मगर, बुधवार सुबह प्रचंड ने घोषणा की, कि पहले संसद में विश्वास मत करा लेते हैं, फिर मैं कुर्सी छोड़ूंगा। एक साल 180 दिनों से प्रचंड सत्ता में हैं। तीसरे टर्म प्रधानमंत्री पद पर बने रहना कितना कठिन होता है, उसे यों समझा जाये कि अब तक उन्हें चार बार विश्वास मत हासिल करना पड़ा है। आखिरी बार 20 मई, 2024 को प्रचंड को विश्वास मत हासिल करना पड़ा था, तब उपेन्द्र यादव के नेतृत्व वाली जनता समाजवादी पार्टी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। बुधवार शाम एमाले ने समर्थन वापसी की घोषणा कर दी।

ब्रह्मा चेलानी

अमेरिका की भारत-नीति दिन-ब-दिन अधिक विद्वेषपूर्ण होती जा रही है, लेकिन उसे यह मालूम होना चाहिए कि दीर्घकालिक अमेरिकी रणनीतिक हितों के लिए भारत से अधिक महत्वपूर्ण कोई और शक्ति नहीं है। क्योंकि जनसंख्या, प्रशांत क्षेत्र में शक्ति-संतुलन बनाए रखने के लिए भारत के साथ साझेदारी को निर्णायक माना है। यह नीति कभी सिर्फ भाषणबाजी तक ही सीमित नहीं रही थी। पिछले एक दशक में तो अमेरिका-भारत सुरक्षा संबंध तेजी से गहराए थे- विशेषकर सैन्य इंटर-ऑपरेबिलिटी, खुफिया सहयोग भी स्पष्ट है रू भारत आज किसी भी अन्य देश की तुलना में अमेरिका के साथ अधिक सैन्य अभ्यास करता है और अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन चुका है। लेकिन इसी प्रक्रिया के बीच अमेरिका ने भारत को सतर्क रहने के कई कारण भी दिए। अफगानिस्तान से उसका

भौगोलिक स्थिति और सैन्य क्षमता- जिनमें परमाणु क्षमता भी शामिल है- के लिहाज से भारत एकमात्र ऐसा देश है, जो एशिया पर प्रभुत्व जमाने और अमेरिका के वर्चस्व को बेदखल करने की चीन की कोशिशों को चुनौती दे सकता है। जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के कार्यकाल से ही वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने भारत-और तकनीकी लेनदेन के स्तर पर। वास्तव में, भारत-अमेरिका रिश्तों में बढ़त का एक हिस्सा तो ट्रम्प के पहले कार्यकाल में घटा था। चीन पर दबाव बढ़ाने और पाकिस्तान को दी जाने वाली सुरक्षा सहायता घटाने के साथ ही ट्रम्प ने भारत के साथ सहयोग को बढ़ाया, जो उनकी इंडो-पैसिफिक रणनीति के केंद्र में था। इसका असर अव्यवस्थित पलायन- जो बाइडेन के कार्यकाल में हुआ लेकिन जिसकी बुनियाद ट्रम्प द्वारा किए समझौते से पड़ी थी- ने अमेरिकी नेतृत्व की समझदारी और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि इसने अफगानिस्तान को फिर से तालिबान के हवाले कर दिया। चिंताएं 2022 में तब और बढ़ीं, जब बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान को आईएमएफ से बेलआउट दिलाने में मदद की और फिर उसके एफ-16 बेड़े के आधुनिकीकरण के लिए 45 करोड़ डॉलर की भी मंजूरी दे दी। ट्रम्प ने भी पाकिस्तान के प्रति इस झुकाव को और तेज ही किया है, जिसका एक उदाहरण उससे की गई क्रिप्टोकरेंसी डील है। अमेरिका ने अकसर भारत के हितों की अनदेखी की है। इसके बावजूद रूस पर लगाए प्रतिबंधों को लागू कराने के मामले में वह भारत से पूरी निष्ठा की उम्मीद करता रहा। भारत इससे सहमत नहीं हुआ और उसने डिस्काउंटेड दरों पर रूसी तेल की खरीद बढ़ा दी। भारत को सुदूर यूरोप में चल रहे किसी संघर्ष के लिए अपने राष्ट्रीय हितों की बलि देने का कोई कारण नहीं दिखा, खासकर तब, जब रूस पर पश्चिमी दबाव का सबसे बड़ा लाभार्थी चीन था। भारत इस समीकरण को पहले भी देख चुका है। 2019 में जब ट्रम्प ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए तो भारत अपने सबसे सस्ते और भरोसेमंद ऊर्जा स्रोतों में से एक से वंचित हो गया था। चीन ने इसका पूरा फायदा उठाया। उसने ईरानी कच्चा तेल भारी छूट पर खरीदा और वहां अपनी सुरक्षा मौजूदगी बढ़ाई। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद भी यही पैटर्न उभरा। पश्चिमी बाजारों से रूस को अलग कर देने के बाद उस पर लगाए प्रतिबंधों ने उसे चीन पर आर्थिक रूप से निर्भर बना दिया, जिससे चीन को रूस से आने वाले ऊर्जा-आपूर्ति मार्गों को मजबूत करने की क्षमता मिल गई। अब चीन जानता है कि ताइवान पर कार्रवाई करने पर भी रूसी ऊर्जा तक उसकी पहुंच नहीं घटेगी। इस बार भारत ने भी रूसी तेल पर उपलब्ध छूट का लाभ उठाया। अमेरिका भारत को अपने लिए जरूरी बताता है, लेकिन उसके हितों की अनदेखी भी करता है। वह चाहता है कि भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उसकी रणनीति का आधार बने, लेकिन वो ऐसी नीतियां भी अपनाता है, जो भारत की आर्थिक क्षमता, क्षेत्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को सीधे नुकसान पहुंचाती हैं। यही कारण है कि आज भारत अमेरिका के प्रति अविश्वास से भर गया है और उसे रूस से संबंध मजबूत करने को मजबूर होना पड़ रहा है। अमेरिका हमारे साथ अच्छे रिश्ते चाहता है तो उसे हमें बराबरी का दर्जा देना होगा। अमेरिका भारत को अपने लिए जरूरी बताता है, लेकिन उसके हितों की अनदेखी भी करता है। वह चाहता है कि भारत इंडो-पैसिफिक में उसकी रणनीति का आधार बने, लेकिन वो ऐसी नीतियां भी अपनाता है, जो हमें क्षति पहुंचाती हैं।

जो चीजें हमारे यहां नहीं बनतीं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है

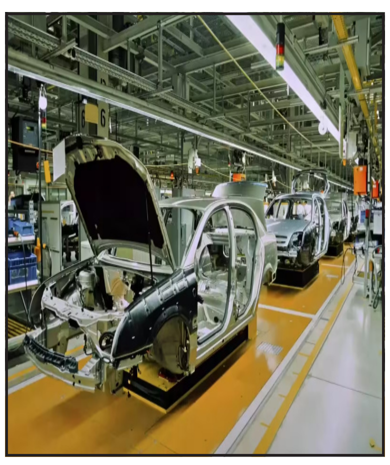

स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उन्हें स्वीकृत 500 रुपये की सरकारी पेंशन लेने से भी उन्होंने यह कहकर मना कर दिया था कि उन्होंने आजादी की लड़ाई पेंशन के लिए थोड़े ही लड़ी थी। खुद्दार तो वे इतने थे कि उन्हें अपनी संतानों, परिजनों व शुभचिंतकों से किसी भी रूप में आर्थिक सहायता लेना गवारा नहीं था। सरकार द्वारा घर देने के प्रस्ताव को भी उन्होंने ठुकरा दिया था। उनके पास अपना घर तक नहीं था तो कार या कोई और वाहन होने का सवाल ही नहीं था। इसलिए राजधानी दिल्ली में वे प्रायः बसों से आते-जाते दिखाई देते थे। बाद में उनकी अहमदाबाद वासी बेटी से उनकी दुर्दशा नहीं देखी गई तो वह उन्हें किसी तरह समझा-बुझाकर अपने साथ ले गईं। वर्ष 1998 में 15 जनवरी को अपने सौवें जन्मदिन से कुछ महीनों पहले उन्होंने वहीं अंतिम सांस ली। निधन से कोई साल भर पहले 1997 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया गया, जबकि पद्मविभूषण से पहले से विभूषित किया जा चुका था। अपने मंत्रिकाल में वे भ्रष्टाचार को लेकर इतने असहिष्णु थे कि भ्रष्टाचारी कितना भी प्रभावशाली या अपना क्यों न हो, उसे बख्शते नहीं थे। एक बार इसी के चलते उन्हें अपना मंत्री पद भी गंवा देना पड़ा था। यह जानना भी दिलचस्प है कि वे जितने बड़े राजनेता, उतने ही अच्छे अर्थशास्त्र के जानकार व लेखक भी थे। उन्होंने कई किताबें तो लिखी ही हैं, श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा और 1947 में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

डॉ. अरुणा शर्मा

स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य यों तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह तभी सफल हो सकता है, जब हमारी नीतियां गुणवत्तापूर्ण मैन्युफैक्चरिंग और ऐसी चीजों के उत्पादन को बढ़ावा दें, जिनका निर्माण अभी भारत में नहीं हो रहा है। जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक तो हमारे आयात में ही इजाफा होगा।ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के नाम पर गुणवत्ता नियंत्रण को कमजोर करने के नए आदेश क्या यह दिखाते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अब क्वालिटी की अहमियत नहीं रही? यह ना भूलें कि एशियन टाइगर्स की श्रेणी में आने वाले देश (हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान) विकसित अर्थव्यवस्था तब बने, जब उन्होंने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों में निवेश किया और अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए इनोवेशन किए। दूसरी तरफ, गुणवत्ता में कमी का असर यह होने वाला है कि खराब क्वालिटी वाले उत्पाद हमारे बाजार में भेजे जाएंगे, जो हमारे घरेलू उत्पादन को नुकसान पहुंचाएंगे। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हर उत्पाद गुणवत्ता वाला हो और आयात के स्थान पर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। यदि दुनिया में ये संदेश चला गया कि हमारे यहां गुणवत्ता की कसौटी अनिवार्य नहीं है तो भारत टेक्स्टाइल्स, स्टील, केमिकल आधारित उत्पादों जैसे फार्मा और अन्य उपयोगी वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग का डम्पिंग ग्राउंड बन सकता है। वास्तव में इस तरह के अदूरदर्शी निर्देश हमारी आत्मनिर्भरता और हमारे विश्वगुरु कहलाने की आकांक्षाओं पर प्रतिकूल असर डालते हैं। घरेलू बाजार में दबदबे और निर्यात के लिए उत्पादों की गुणवत्ता सबसे महत्वपूर्ण है और आयात से गुणवत्ता नियंत्रण हटाना इसी चीज को कमजोर करता है। बहरहाल, नई एकीकृत चार श्रम संहिताएं स्वागतयोग्य हैं। इनमें गिग वर्कर्स समेत सभी तरह के श्रमिकों को शामिल किया गया है। उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने की कोशिश की गई है। लेकिन इसमें न्यूनतम मजदूरी पर ही ज्यादा जोर है, जबकि बेहतर जीवन सुनिश्चित करने वाली मजदूरी अभी भी अपेक्षित है। सवाल यह है कि हम ये सुनिश्चित करें कि श्रमिकों से नियमानुसार और शोषण-रहित ही काम लिया जाए और हम पहले से नाजुक चल रहे श्रम बाजार को मजबूत करने में सक्षम बनें। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संतुलन बनाने का उद्देश्य गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भविष्य निधि, ईएसआईसी और बीमा जैसी सुरक्षा देना है, ताकि एक से अधिक नियोक्ताओं के साथ काम कर रहे लोगों के लिए पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम जैसी नई कार्य-प्रणालियों को भी सुरक्षा के दायरे में लाया जा सके। अब प्रत्येक राज्य अपने नियम अधिसूचित करेगा और माना जा रहा है कि कुछ सहमत सिद्धांतों पर एकरूपता रहेगी। खासकर, असंगठित क्षेत्र के 90 प्रतिशत श्रमिकों के लिए। इधर, छोटे उद्योगों के लिए भी निवेश की सीमा 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर की सीमा 100 करोड़ रुपए तक बढ़ाकर उन्हें दुबारा परिभाषित किया गया है। इससे इन इकाइयों पर अनुपालन का बोझ कम हुआ है और 300 कर्मचारियों तक के उद्योगों को भर्ती और यहां तक कि छंटनी में भी आसानी हुई है। यहां विशेष ध्यान देना होगा कि कामगारों का शोषण न हो। डिजिटल फाइलिंग का बोझ इससे ऊपर वाले उद्योगों के लिए है और वह भी स्वघोषणा पर आधारित है। इस प्रकार, चार श्रम संहिताएं, लघु उद्योगों की परिभाषा में संशोधन और सबसे महत्वपूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण में ढील एक समग्र दृष्टिकोण के तौर पर एक-दूसरे के विरोधाभासी हैं। श्रम संहिता की सुरक्षा लचीलेपन के कारण अनौपचारिक श्रम अदालतों के बड़े हिस्से को उनके अधिकारों से वंचित कर देगी। कैजुअलाइजेशन को नियोक्ताओं के विवेक पर छोड़ा गया है, जिससे स्थायी नौकरियों के बजाय ठेका आधारित श्रम को अधिक बढ़ावा मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत करने के लिए ऐसा समग्र दृष्टिकोण आवश्यक है, जिसमें गुणवत्ता को ही की-फैक्टर माना जाए। बेहतर कौशल वाले श्रमिक हों, उनके अधिकार सुरक्षित रखे जाएं और बेहतर इनोवेशन को बढ़ावा मिले।

देश की राजधानी किसी बुरे सपने से कम नहीं है

देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र भीषण प्रदूषण की मार झेल रहा है। यही वजह है कि प्रदूषण की भयावहता तमाम क्षेत्रों में तरक्की को मुंह चिढ़ा रही है। सरकारों और राजनीतिक दलों की बला से प्रदूषण प्रभावित इन क्षेत्रों के करोड़ों लोगों बेशक तिल–तिल करके मरते रहें। इसके विपरीत नेताओं का सरोकार सिर्फ चुनाव जीतने भर तक सीमित रह गया है। सत्तारुढ़ और विपक्षी दल इस मुद्दे पर चिंता जताने तक सीमित हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरूआत में विपक्ष के कुछ सांसदों ने अपने चेहरों पर मॉस्क लगाया और प्रदूषण के खिलाफ नारे लिखे तख्खियां और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया। एक बैनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी जिस पर लिखा था 'मौसम का मजा लीजिए'। सरकारी नजरिए से देखें तो राजधानी दिल्ली और आस–पास के क्षेत्रों में प्रदूषण लाइलाज समस्या बन चुका है। हर साल सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली का इलाका गैस चैंबर बन जाता है। इस बात से सत्तारुढ़ और विपक्षी दल अनजान नहीं हैं। इसके बावजूद कोरी बयानबाजी के अलावा लोगों को उनके हाल पर छोड़ रखा है। दिल?ली का औसत एक?यूआई लेवल 377 तक दर्ज हो चुका है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन की समस?या देखने को मिल रही है। आनंद विहार, बवाना, चांदनी चौक जहांगीर पुरी, जवाहरलाल नेहरू स?टेडियम और नेहरू नगर में एक?यूआई लेवल 400 के पार तक पहुंच गया। दिल?ली की हवा में घुला जहर कम कब होगा।

सरकारी नजरिए से देखें तो राजधानी दिल्ली और आस–पास के क्षेत्रों में प्रदूषण लाइलाज समस्या बन चुका है। हर साल सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली का इलाका गैस चैंबर बन जाता है। इस बात से सत्तारुढ़ और विपक्षी दल अनजान नहीं हैं। इसके बावजूद कोरी बयानबाजी के अलावा लोगों को उनके हाल पर छोड़ रखा है। देश में वोट बैंक की राजनीतिक के समक्ष पर्यावरण प्रदूषण जैसे मुद्दे हाशिए पर धकेले जाते रहे हैं। राजनीतिक दल इसे समस्या तो मानते हैं किन्तु इसके स्थायी निदान के लिए न तो कोई कार्ययोजना है और न ही इच्छाशक्ति। देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी परियोजना क्षेत्र भीषण प्रदूषण की मार झेल रहा है। यही वजह है कि प्रदूषण की भयावहता तमाम क्षेत्रों में तरक्की को मुंह चिढ़ा रही है। सरकारों और राजनीतिक दलों की बला से प्रदूषण प्रभावित इन क्षेत्रों के करोड़ों लोगों बेशक तिल–तिल करके मरते रहें। इसके विपरीत नेताओं का सरोकार सिर्फ चुनाव जीतने भर तक सीमित रह गया है। सत्तारुढ़ और विपक्षी दल इस मुद्दे पर चिंता जताने तक सीमित हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरूआत में विपक्ष के कुछ सांसदों ने अपने चेहरों पर मॉस्क लगाया और प्रदूषण के खिलाफ नारे लिखे तख्खियां और बैनर लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों का नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया। एक बैनर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी जिस पर लिखा था 'मौसम का मजा लीजिए'। सरकारी नजरिए से देखें तो राजधानी दिल्ली और आस–पास के क्षेत्रों में प्रदूषण लाइलाज समस्या बन चुका है। हर साल सर्दी का मौसम आते ही दिल्ली का इलाका गैस चैंबर बन जाता है। इस बात से सत्तारुढ़ और विपक्षी दल अनजान नहीं हैं। इसके बावजूद कोरी बयानबाजी के अलावा लोगों को उनके हाल पर छोड़ रखा है। दिल?ली का औसत एक?यूआई लेवल 377 तक दर्ज हो चुका है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में दिक?कत और आंखों में जलन की समस?या देखने को मिल रही है। आनंद विहार, बवाना, चांदनी चौक जहांगीर पुरी, जवाहरलाल नेहरू स?टेडियम और नेहरू नगर में एक?यूआई लेवल 400 के पार तक पहुंच गया। दिल?ली की हवा में घुला जहर कम कब होगा। इस सवाल का जवाब इस समय शायद किसी के पास नहीं है। शायद इसीलिए डॉक?टरों ने साफ कह दिया है कि बच?चों की सेहत ठीक रखना चाहते हैं, तो कुछ दिनों के लिए दिल?ली छोड़ दीजिए। दिल्ली में एयर क्वॉलिटी मैनेजमेंट के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम (डीएसएस) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में प्रदूषण के बड़े कारण ट्रांसपोर्ट, पराली है। गाड़ियों से फैले प्रदूषण का हिस्सा 18.42% था। आंकड़ों के हिसाब से 16.31% प्रदूषण के अन्य सोर्स हैं, जिसमें आतिशबाजी, डीजल जनरेटर जैसे सोर्स शामिल है। शादियों के सीजन की वजह से आतिशबाजी हो भी रही हैं। अगले तीन दिन इन अन्य सोर्स का प्रदूषण का हिस्सा और बढ़कर 43.4% तक जाने का अनुमान है। दिल्ली में एक्यूआई 400 तक के खतरानक स्तर को छू चुका है, जो वायु प्रदूषण की गंभीर हालत दिखाता है। वहीं मुंबई में भी ये 200 के करीब पहुंच गया था, जिसके बाद वहां ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप 4) लागू किया गया। हालांकि दिल्ली में अभी ग्रैप 4 लागू नहीं किया गया। उल्टे दिल्ली एनसीआर में 26 नवंबर को ग्रैप 3 की पाबंदियां भी वापस ले ली गई थीं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) ने शहर में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी थी। देवनार, मलाड, बोरीवली, अंधेरी ईस्ट, नेवी नगर, पवई और मुलुंड जैसे इलाकों में प्रदूषण की खराब स्थिति के बाद ये फैसला लिया गया था। दिल्ली में प्रदूषण पराली जलने, वाहनों के धुएं और कारखानों से निकलने वाला कार्बन उत्सर्जन जिम्मेदार है। हवाओं की रफ्तार धीमी पड़ने से हालात और खराब हो जाते हैं। हालांकि मुंबई और अन्य समुद्री इलाकों में प्रदूषण की स्थिति बेहतर रहती है, क्योंकि वहां हवा चलने के कारण प्रदूषणकारी तत्व शहर से दूर चले जाते हैं। मुंबई में मेट्रो, फ्लाईओवर जैसे बड़े निर्माण कार्य, वाहनों की बढ़ती तादाद और कचरा जलाने जैसी वजहों से हालत बिगड़ी है। मुंबई जैसे समुद्री इलाकों में एक्यूआई बढ़ना खतरे की घंटी है। मुंबई में ग्रैप-4 की पाबंदियों के बाद एक्यूआई 150 से नीचे आ गया, जबकि दिल?ली की हवा में अब भी दम घुट रहा है। मुंबई की हवा अब सांस लेने लायक हो गई है। यहां कई जगह एक?यूआई लेवल 100 के आसपास हो गई। हालांकि, दिल?ली में एक?यूआई लेवल अब भी कई जगह 400 के पार है। हवा की गति बढ़ने और पानी छिड़काव जैसे उपायों से मुंबई में हवा की गति बढ़ने और पानी छिड़काव जैसे उपायों से मुंबई में एक्यूआई स्तर 150 से नीचे आने में मदद मिली। दुनिया भर में वायु प्रदूषण को मापने वाली अंतरराष्ट्रीय संस्था आईक्यूएआईआर की नवीनतम लाइव रैंकिंग में भारत की राजधानी दिल्ली इस सूची में पहले स्थान पर रही। जबकि दूसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद 251 के एक्यूआइ के साथ दर्ज है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का लाहौर (एक्यूआइ 215), चौथे पायदान पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका 211, एक्यूआइ के साथ है। भारत का कोलकाता भी 211 के एक्यूआइ के साथ पांचवें स्थान पर है। देश की राजधानी दिल्ली में एयर इमरजेंसी है। राजधानी दिल्ली गैस चैंबर बन गई है। राजधानी दिल्ली हांफ रही है, खांस रही है। दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है। दिल्ली में हर व्यक्ति हर पल अपने फेफड़ों में जहर भर रहा है। दिल्ली को डिटॉक्स करने की जरूरत है। दिल्ली-एनसीआर इलाके की इन दिनों जैसे बस यही पहचान बन गई है। देश ही नहीं दुनिया भर के अखबारों-समाचार चैनलों, वेबसाइट्स में दिल्ली की हवा सुर्खियों में है। दिल?ली एनसीआर में इस समय धुंध नहीं बल्कि, हवा में मौजूद धूल के कारण है, वो धूल जो कभी कंस्ट्रक्शन की वजह से कभी पोल्यूशन की वजह से कभी पराली की वजह से घटना हो रही है। ये लटके हुए कण जो धूल के हैं ये पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे महीन कण इसमें शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि एक दिन की दिल्ली की हवा में सांस लेना करीब 50 सिगरेट के पीने के बराबर है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली की हवा का क्या हाल है। रोज पीने-उपयोग करने वाला भूजल भी अब दिल्ली में सुरक्षित नहीं बचा है। केंद्रीय भूमिजल बोर्ड की नई रिपोर्ट बताती है कि इस पानी में यूरेनियम जैसे खतरनाक तत्वों के साथ नाइट्रेट, फ्लोराइड, लेड और ज्यादा नमक तक मिला हुआ है।

अंडर-19 एशिया कप में 14 साल के वैभव का धमाका, 56 गेंदों में लगाई सेंचुरी; 2025 का छठा शतक

दुबई : यह सूर्यवंशी का लिस्ट-ए क्रिकेट में दूसरा शतक था। इससे पहले वह इंग्लैंड में भी एक शतक जमा चुके हैं। 2025 में यह उनका छठा शतक है, जो उनकी जबरदस्त निरंतरता को दशार्ता है। भारत के उभरते युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए शुक्रवार, 12 दिसंबर को दुबई के आईसीसी अकादमी मैदान पर अंडर-19 एशिया कप के शुरूआती मैच में यूएई के खिलाफ सिर्फ 56 गेंदों में तूफानी शतक ठोक दिया। 14 वर्षीय वैभव ने भारत को बेहतरीन शुरूआत दिलाई। भारत को पहले बल्लेबाजी मिली और सूर्यवंशी ने शुरूआत से ही दबदबा बनाया। चौकों-छक्कों से लबालब पारी वैभव ने 95 गेंदों में 171 रन की पारी खेली और इस पारी में नौ चौके और 14 छक्के लगाए। उन्होंने शुरूआत में सधी हुई बल्लेबाजी की और छठी गेंद पर चौका लगाकर खाता खोला। इसके बाद उन्होंने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अली असगर को अगले ओवर में दो छक्के जड़ते हुए तेजी पकड़ ली।

'नाव पर लगाया एक दूसरे को गले', पहली बार रिश्ते पर खुलकर बोले वीर पहाड़िया और तारा सुतारिया

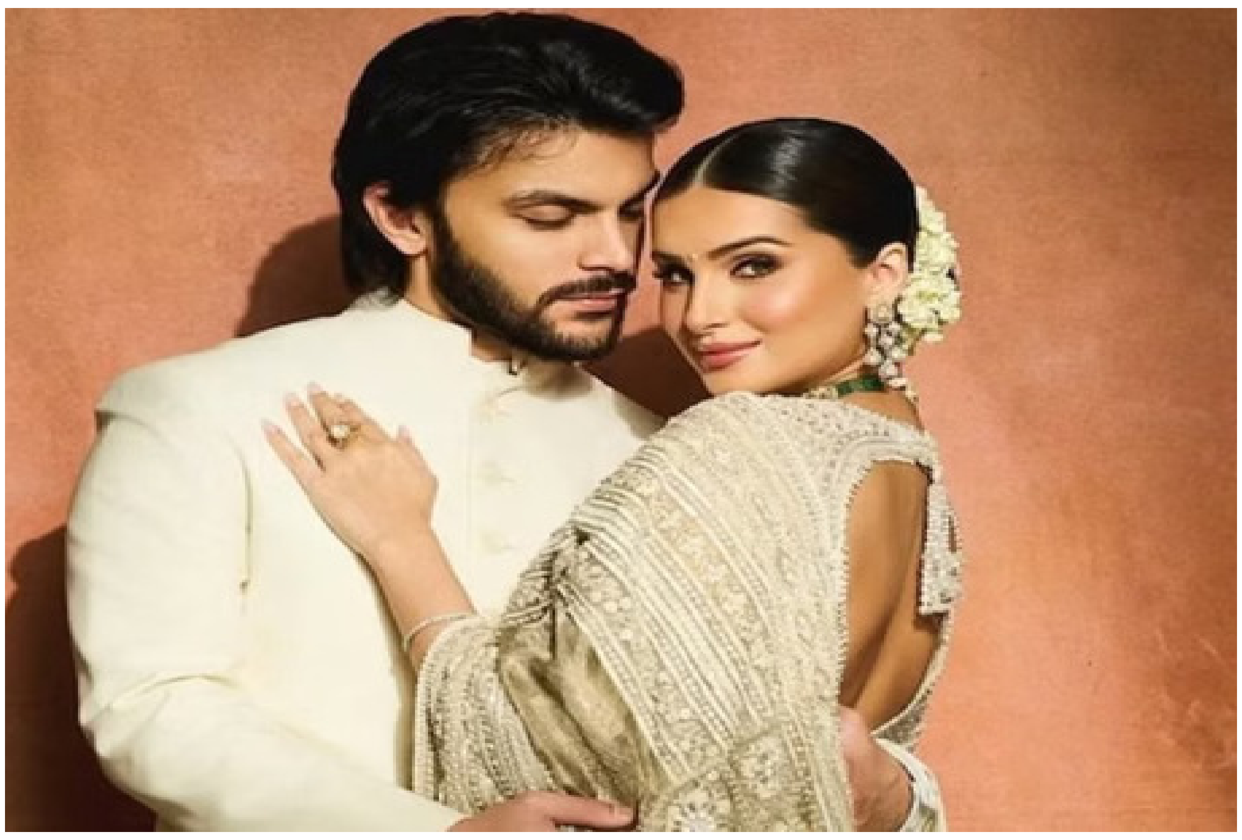

बॉलीवुड के नए-नवेले कपल वीर पहाड़िया ओर तारा सुतारिया ने पहली बार अपने रिश्ते को लेकर सार्वजनिक तौर पर खुलकर बात की है। दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हुए पलों को याद किया है। अभिनेत्री तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया पिछले काफी समय से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर साथ बिताए पलों की झलक और तारा के फैशन इवेंट्स में वीर की मौजूदगी ने पहले ही कयासों को हवा दे दी थी, लेकिन दिवाली पर दोनों के फोटोशूट ने काफी हद तक रिश्ते पर मुहर लगा दी। अब तारा और वीर ने पहली बार किसी इंटरव्यू में खुलकर एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप पर खुलकर बात की है। रिश्ते पर खुलकर बोले वीर-तारा दोनों ने हाल ही में 'ट्रैवल-लेजर इंडिया' को दिए एक इंटरव्यू में अपने शुरूआती दिनों को याद करते हुए बताया कि उनका रिश्ता पहले दिन से ही ईमानदारी से शुरू हुआ है। वीर के मुताबिक, पहली ही डेट से दोनों ने अपने जज्बातों को छुपाने की कोशिश नहीं की और जहां भी रहे, जैसे थे वैसे ही रहे। वीर ने साझा किया पहली डेट का पल पहली डेट का जिक्र करते हुए वीर ने एक बेहद खास पल साझा किया। उन्होंने बताया कि वो शाम उनके लिए यादगार बन गई जब उन्होंने पियानो बजाया और तारा ने गाना गाया। साथ बिताया गया वह समय उनके लिए रिश्ते की पहली मजबूत नींव साबित हुआ। वहीं तारा का मानना है कि किसी एक पल ने नहीं, बल्कि वक्त के साथ एक-दूसरे का साथ निभाने ने उनके रिश्ते को खास बनाया। उनके शब्दों में, मुश्किल और अच्छे दोनों दौर में साथ खड़े रहना ही उनके कनेक्शन की असली पहचान है। दोनों ने पहले ट्रिप का भी किया जिक्र जहां पहली डेट ने दिलों को करीब लाया, वहीं पहली ट्रिप ने रिश्ते को और गहरा किया। तारा ने खुलासा किया कि उनकी पहली वेकेशन इटली के खूबसूरत आइल ऑफ कप्री में हुई। इस जगह से जुड़ी एक पारिवारिक मान्यता का जिक्र करते हुए तारा ने बताया कि उनकी मां हमेशा कहती थीं कि कप्री वह जगह है, जहां इंसान अपने सबसे खास दोस्त और प्रिय के साथ जाता है। कहा जाता है कि अगर वहां नाव पर किसी को गले लगाया जाए, तो रिश्ता हमेशा खास बना रहता है। तारा और वीर ने भी वही किया, जिसे वह अपने रिश्ते के लिए शुभ मानती हैं।

सुपरगर्ल का टीजर रिलीज, एक्शन अंदाज में नजर आईं मिली एल्कॉक; जानिए थिएटर में कब आएगी फिल्म

सुपरमैन सीरीज की फिल्म सुपरगर्ल में लीड रोल में वुमन कैरेक्टर है। मिली एल्कॉक सुपरमैन स्टाइल का एक्शन फिल्म में कर रही हैं। हाल ही में इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ।

डीसी स्टूडियोज की नई फिल्म सुपरगर्ल अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हाल ही में इस फिल्म का टीजर-ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज किया है। एक्शन से भरपूर इस टीजर ने फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। जानिए, सुपरगर्ल के टीजर में क्या कुछ खास दिखा? सुपरगर्ल बनीं मिली एल्कॉक टीजर-ट्रेलर की शुरूआत एक आम टीनएज लड़की से होती है, जिसकी जिंदगी काफी अस्त-व्यस्त है। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बनती हैं कि उसे अपनी सुपरपावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, बुरे लोगों से दुनिया को बचाना पड़ता है। इस काम में उसकी मदद एक अनजान लड़की भी करती है। फिल्म ह्यसुपरगर्लह्न को क्रेग गिलेस्पी ने निर्देशित किया है। कब रिलीज होगी फिल्म फिल्म के टीजर-ट्रेलर के साथ मेकर्स ने रिलीज डेट भी शेयर की है। अगले साल यह फिल्म रिलीज होगी। इस रिलीज की तारीख जून 2026 है। फिल्म 'सुपरगर्ल' में भी 'सुपरमैन' के लेवल का एक्शन और वीएफएक्स देखने को मिल रहा है। विलेन भी काफी खूंखार नजर आ रहे हैं। बैकग्राउंड स्कोर भी एक्शन सीन्स पर परफेक्ट बैठ रहा है।

हेमा मालिनी को इस नाम से बुलाते हैं सनी-बॉबी देओल, ड्रीम गर्ल ने खुद किया था बड़ा खुलासा

बॉलीवुड की जानी-मानी जोड़ियों में से एक हैं हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी। पर्दे पर इनकी जोड़ी हमेशा हिट रही, वहीं रियल लाइफ में भी इनके रिश्ते की चर्चा रही है। दोनों की मुलाकात फिल्म सेट पर हुई थी और काम के दौरान उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। उस समय धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनके चार बच्चे सनी, बॉबी, अजीता और विजेता थे। शुरूआती दिनों में देओल परिवार इस रिश्ते को लेकर नाराज था, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया।हेमा मालिनी ने 25 साल पहले दूरदर्शन के शो श्हेलो डीडीश में बताया था कि सनी और बॉबी देओल उन्हें हेमा जी कहकर बुलाते हैं। उन्होंने इस दौरान कहा कि दोनों बहुत अच्छे हैं और उनके साथ हमेशा सम्मान से पेश आते हैं। हेमा मालिनी ने कई इंटरव्यूज में भी देओल परिवार के साथ अपने रिश्ते की बात की है और बताया कि सनी और बॉबी दोनों प्यार और सम्मान से पेश आते हैं। हालांकि, धर्मेंद्र के निधन के बाद खबरें आईं कि हेमा मालिनी और देओल परिवार के बीच रिश्तों में दूरी आ गई है। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार और प्रेयर मीट में दोनों परिवार अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे थे। दिल्ली में हाल ही में रखी गई प्रेयर मीट में भी सनी-बॉबी देओल का परिवार शामिल नहीं दिखा। हालांकि, इस मामले पर किसी भी पक्ष से आधिकारिक बयान नहीं आया है। हेमा मालिनी 77 साल की हैं, सनी देओल 68 और बॉबी देओल 56 साल के हैं। सनी और हेमा के बीच उम्र का अंतर 9 साल है, जबकि बॉबी देओल हेमा से 21 साल छोटे हैं। धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर, 2025 को हुआ। 89 साल की उम्र में उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ। अंतिम समय में उन्हें सांस लेने में परेशानी थी और वे वेंटिलेटर पर थे। धर्मेंद्र की मौत ने परिवार और फैंस को गहरे दुख में डाला। धर्मेंद्र को आखिरी बार अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म श्इक्कीसश में देखा जाएगा। यह फिल्म क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। फिल्म में जयदीप अहलावत समेत अन्य कलाकार भी अहम भूमिका में हैं। धर्मेंद्र को आखिरी बार स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस बेहद उत्साहित हैं।

पाकिस्तान सहित इन 6 देशों में बैन है धुरंधर फिल्म, जानें इसके पीछे की चौंका देने वाली बड़ी वजह

आदित्य धर के निर्देशन में बनी स्पाई एक्शन थ्रिलर धुरंधर ने रिलीज के पहले ही हफ्ते में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है। 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने सातवें दिन भी 27 करोड़ रुपये की कमाई की और कुल कलेक्शन 207.25 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स से सजी यह फिल्म आपरेशन लायन से प्रेरित है। फिल्म की लंबाई 3 घंटे 30 मिनट है, लेकिन इसके गाने, कहानी, एक्शन और निर्देशन को दर्शकों ने खूब सराहा है। फिल्म का ओपनिंग वीकेंड भी शानदार रहा। पहले दिन 27.60 करोड़, दूसरे दिन 33.10 करोड़ और तीसरे दिन 44.70 करोड़ की कमाई हुई। चौथे दिन 24.30 करोड़ के साथ वीकडे में भी फिल्म ने स्थिरता दिखाई। कुल मिलाकर यह 2025 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बन गई है, जिसने श्सैयाराश को पीछे छोड़ दिया। हालांकि, ग्लोबल मार्केट में फिल्म को बैन का सामना करना पड़ा। फिल्म को पाकिस्तान सहित 6 अन्य देशों में रिलीज की अनुमति नहीं मिली। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में इसे रिलीज नहीं किया गया। एक सोर्स के मुताबिक, फिल्म को एंटी पाकिस्तान मुवी माना गया, इसलिए थीम की वजह से रिलीज को मंजूरी नहीं मिली। फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन चार दिनों में 44.07 करोड़ रुपये रहा, जो गल्फ मार्केट से अधिक होता अगर रिलीज मिली होती। पहले भी कई भारतीय फिल्में पाकिस्तान-संबंधित कंटेंट के कारण गल्फ में रिलीज नहीं हो पाईं। 2025 में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर भी इसी वजह से अधिकांश गल्फ देशों में बैन रही। इसी तरह स्काई फोर्स, द डिप्लोमैट, आर्टिकल 370, टाइगर 3 और द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में भी मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में प्रतिबंधित रहीं। धुरंधर की सफलता के बाद मेकर्स ने धुरंधर 2 की घोषणा कर दी है। यह फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी। उसी दिन यश की टॉक्सिक भी रिलीज होने जा रही है। दो बड़ी फिल्मों के रिलीज होने से बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों के लिए दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। इस प्रकार, ग्लोबल मार्केट में बैन के बावजूद धुरंधर भारत में दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय साबित हुई है और बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है।

रकुल प्रीत से लेकर मनारा चोपड़ा तक का ग्लैमरस अंदाज, अवॉर्ड इवेंट में दिखा फैशन का जलवा

मुंबई में हर दिन अवॉर्ड फंक्शन, फैशन इवेंट होते हैं। एक अवॉर्ड नाइट

में रकुल प्रीत से लेकर मनारा चोपड़ा तक नजर आईं। इन एक्ट्रेसेस के लुक ने महफिल ही लूट ली। देखें, इस इवेंट में और कौन-कौन शामिल हुआ? अवॉर्ड फंक्शन में एक्ट्रेसेस के लुक भी, फैशन स्टाइल भी काफी चर्चा में रहते हैं। शुक्रवार को मुंबई में एक अवॉर्ड फंक्शन में रकुल प्रीत और मनारा चोपड़ा के अलावा कई एक्ट्रेसेस का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला। इनके स्टाइल पर फैंस भी फिदा नजर आए।

क्रिसमस पर लौटेगा क्लासिक बॉलीवुड रोमांस, कार्तिक, अनन्या की लव स्टोरी

इस क्रिसमस दर्शकों को मिलने वाला है एक खास सिनेमाई तोहफा। कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे अपनी नई फिल्म तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी में एक बार फिर साथ नजर आएंगे। यह फिल्म 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी और क्लासिक बॉलीवुड रोमांस की उसी पुरानी, मीठी वाइब को वापस लाने का वादा करती है, जिसे दर्शक बेहद पसंद करते रहे हैं। दोनों की सहज, ताजगी भरी केमिस्ट्री एक बार फिर बड़े पर्दे पर जादू

बिखेरने वाली है। फिल्म में रोमांस बिल्कुल पुरानी रूह वाला है सीधा-सादा, दिल को छूने वाला और बिना किसी भारी-भरकम ड्रामा के। कार्तिक अपनी ट्रेडमार्क रोमांटिक-कॉमेडी स्टाइल में नजर आएंगे, वहीं अनन्या अपनी मजबूत और ग्राउंडेड परफॉर्मेंस के साथ कहानी में एक ताजा, ईमानदार एहसास जोड़ेंगी। दोनों का रिश्ता स्क्रीन पर गर्मजोशी, हल्की-फुल्की नोकझोंक और दिल छू लेने वाली मासूमियत से भरा नजर आएगा, जो क्रिसमस की रोशनी में और भी खूबसूरत बन जाता है। क्रोएशिया और भारत की मनमोहक खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माई गई यह कहानी एक त्योहारों से भरी पोस्टकार्ड जैसी दुनिया तैयार करती है रंगों से सजी, संगीत में लिपटी और ऐसी छोटी-छोटी पलों से भरी, जो चेहरे पर मुस्कान ला दें। निर्देशक समीर विदवान्स द्वारा निर्देशित और धर्मा प्रोडक्शंस व नमः पिक्चर्स द्वारा निर्मित यह फिल्म क्रिसमस 2025 के लिए एक गर्मजोशी भरा, दिल को सुकून देने वाला अनुभव पेश करने वाली है।

एस.एस. राजामौली ने की एकाकी में जॉनर में बदलाव लाने के लिए आशीष चंचलानी की तारीफ

आशिष चंचलानी, जो भारत के सबसे बड़े डिजिटल स्टार्स में से एक हैं और जिनकी पूरे देश में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, उन्होंने अपने करियर में एक बड़ा कदम उठाया है। सालों तक पैरोडी और कॉमिक वीडियोज से लोगों का मनोरंजन करने के बाद, अब उन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में अपनी पहली सीरीज एकाकी के साथ एंट्री की है। हॉरर-कॉमेडी थ्रिलर पर आधारित इस सीरीज के पहले दो एपिसोड रिलीज हो चुके हैं और दर्शकों व क्रिटिक्स दोनों से अच्छी तारीफें बटोर रहे हैं। यह पल इसलिए भी खास है क्योंकि देश के बड़े फिल्ममेकर एस.एस. राजामौली ने भी आशिष को सराहते हुए शुभकामनाएँ दीं। उन्होंने एक्स (पहले ट्विटर) पर आशिष के काम की तारीफ की। कहना गलत नहीं होगा कि आशिष के लिए यह तारीफ उनकी क्रिएटिव सफर में बहुत बड़ा गर्व पल है। एस.एस. राजामौली ने एकाकी के कुछ स्टिल्स शेयर किए और लिखा, वाराणसी के इवेंट में आशिष से मुलाकात हुई थी और अब उन्हें अपनी खुद की लिखी, बनाई और प्रोड्यूस की गई सीरीज के साथ देख कर खुशी हो रही है। रुमांप बहुत अच्छी लग रही है खासकर हॉरर से साइ-फाई में जाने वाला ट्विस्ट। बहुत समझदारी भरा आइडिया। ढेर सारी शुभकामनाएं / ोबींदबीसंदप !!ह्वएकाकी में आशिष चंचलानी राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लीड एक्टर के रूप में कई जिम्मेदारियाँ निभाते दिखते हैं। इससे उनके क्रिएटिव जुनून की गहराई साफ दिखती है। इस सीरीज के लिए उन्होंने अपनी भरोसेमंद टीम को फिर साथ जोड़ा है, कुणाल छाबड़िया को-प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हैं, आकाश दोडेजा पैरेलल लीड निभा रहे हैं, जबकि जशन सिरवानी प्रोजेक्ट को एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में संभाल रहे हैं और तनीश सिरवानी क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में इसकी सोच और लुक तैयार कर रहे हैं। स्क्रीनप्ले को ग्रिशिम नवानी ने मिलकर लिखा है, और लाइन प्रोड्यूसर रितेश सदवानी ने प्रोडक्शन में पूरी मदद दी है। एक अलग तरह का और डूबकर देखने वाला किस्सा देने का वादा करने वाली यह सीरीज, एकाकी, का पहला एपिसोड 27 नवंबर 2025 को आया था और दूसरा एपिसोड 8 दिसंबर 2025 को रिलीज हुआ। दोनों एपिसोड एसीवी स्टूडियोज के यूट्यूब चौनल पर ही एक्सक्लूसिव तौर से रिलीज हुए हैं।

हैप्पी बर्थडे युवराज सिंह: लोगों को कभी हार न मानना सिखाया, 12 नंबर की जर्सी ही क्यों पहनी?

नई दिल्ली : युवराज सिंह केवल क्रिकेटर नहीं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। उन्होंने खेल के मैदान पर और जीवन की लड़ाइयों में कभी हार नहीं मानी। उनका जीवन, 12 नंबर की जर्सी और मैदान पर उनका निडर प्रदर्शन, हर पीढ़ी को यह सिखाता है कि संघर्ष और आत्मविश्वास से किसी भी चुनौती को मात दी जा सकती है। भारत के पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। 12 दिसंबर 1981 को चंडीगढ़ में जन्मे युवराज ने अपने जीवन के 44 साल पूरे कर लिए हैं। मैदान पर वह हमेशा मैच विजेता के रूप में जाने गए। टीम इंडिया के लिए कठिन हालात में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से कई अहम मैच जिताए। वह दो बार भारत की विश्व विजेता क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे और 2011 क्रिकेट विश्व कप में उनकी भूमिका अमूल्य रही। युवराज ने न केवल खेल में बल्कि जीवन की चुनौतियों में भी कभी हार नहीं मानी। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के बाद उन्होंने वापसी की और अपने करियर को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। युवराज का 12 नंबर का करिश्मा युवराज ने अपने करियर में हमेशा 12 नंबर की जर्सी पहनी। यह सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि उनके जीवन और करियर का प्रतीक बन गया।

गैरकानूनी है एच-1बी वीजा पर एक लाख डॉलर की फीस? ट्रंप के फैसले के खिलाफ अमेरिकी राज्य

वॉशिंगटन : क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एच-1बी वीजा शुल्क को बढ़ाकर एक लाख डॉलर करना गैरकानूनी है? ये सवाल इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि अमेरिका के ही 20 राज्यों ने ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आइए जानते है कि क्यों कोर्ट पहुंचे अमेरिकी राज्य और कोर्ट में ऐसी क्या दलील दी, जिससे इस मामले में कानूनी जंग तेज हो गई? अमेरिका में एच-1बी वीजा शुल्क को लेकर ट्रंप प्रशासन का हालिया फैसला अमेरिका में सियासी और कानूनी बहस का बड़ा मुद्दा बन गया है। ट्रंप प्रशासन की तरफ से एच-1बी वीजा पर एक लाख डॉलर की भारी-भरकम फीस लगाने के फैसले के खिलाफ अब खुद अमेरिका के 20 राज्यों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मामले में राज्यों का कहना है कि यह फैसला गैरकानूनी है और इससे स्कूलों, अस्पतालों और अन्य जरूरी सेवाओं में स्टाफ की कमी और गंभीर हो जाएगी। बता दें कि यह मुकदमा होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट (डीएसएस) की उस नीति के खिलाफ है, जिसमें एच-1बी वीजा के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों से बहुत ज्यादा फीस लेने की बात कही गई है। एच-1बी वीजा का इस्तेमाल आमतौर पर अस्पताल, विश्वविद्यालय और सरकारी स्कूल जैसे संस्थान करते हैं, ताकि वे विदेश से कुशल कर्मचारियों को रख सकें। राज्यों की दलील क्या है? राज्यों ने ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में दलील दी है। राज्यों का कहना है कि यह फैसला प्रशासनिक प्रक्रिया कानून का उल्लंघन करता है। राज्यों ने इस बात पर भी जोर दिया कि ट्रंप प्रशासन का ये फैसला अमेरिकी संविधान के भी खिलाफ है। कांग्रेस ने कभी भी इतनी ज्यादा फीस लगाने की अनुमति नहीं दी। राज्यों ने कहा कि पहले एच-1बी वीजा की फीस सिर्फ सिस्टम चलाने के खर्च तक सीमित रहती थी। अभी तक एच-1बी वीजा के लिए कंपनियों को कुल मिलाकर 960 डॉलर से 7,595 डॉलर तक फीस देनी पड़ती है। राज्यों का कहना है कि यह फैसला कांग्रेस की सीमा से बाहर जाकर लिया गया है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर असर इतना ही नहीं राज्यों के अटॉर्नी जनरल्स ने चेतावनी दी है कि इस नई फीस से टीचरों और डॉक्टरों की कमी और गंभीर हो जाएगी। 2024झ्र25 के स्कूल वर्ष में अमेरिका के 74% स्कूल जिलों ने माना कि उन्हें खाली पद भरने में दिक्कत हो रही है। खासकर स्पेशल एजुकेशन, साइंस, ईएसएल/बाइलिंगुअल शिक्षा और विदेशी भाषाओं में। कौन-कौन से राज्य इस केस में शामिल हैं? ट्रंप प्रशासन के खिलाफ कोर्ट पहुंचे 20 राज्यों में कैलिफोर्निया और मैसाचुसेट्स के साथ-साथ एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, हवाई, इलिनॉय, मैरीलैंड, मिशिगन, मिनेसोटा, नेवादा, नॉर्थ कैरोलाइना, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, ओरेगन, रोड आइलैंड, वर्मोंट, वॉशिंगटन और विस्कॉन्सिन जैसे राज्य शामिल है।

मैक्सिको के टैरिफ में भारी बढ़ोतरी के फैसले से भारतीय ऑटो उद्योग में चिंता, क्या होगा आगे!

नई दिल्ली : कार इंपोर्ट पर मेक्सिको की तरफ से टैरिफ में भारी बढ़ोतरी से भारत में बनी गाड़ियों के लगभग 1 अरब डॉलर के एक्सपोर्ट पर खतरा मंडरा रहा है। जिससे वाहन निमार्ताओं को उत्पादन, कीमत और मार्केट स्ट्रेटेजी पर फिर से विचार करना पड़ रहा है। मैक्सिको द्वारा कारों के आयात पर शुल्क को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर अगले साल 50 प्रतिशत करने के फैसले ने भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में हलचल मचा दी है। यह फैसला उन देशों पर लागू होगा जिनके साथ मैक्सिको का मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, और भारत भी इसमें शामिल है। इसके चलते करीब एक अरब डॉलर के भारतीय कार निर्यात पर खतरा मंडराने लगा है। भारतीय ऑटो उद्योग के लिए, जो उत्पादन संतुलन बनाए रखने के लिए निर्यात बाजारों पर काफी हद तक निर्भर रहता है, इसका असर तेजी से और व्यापक रूप में दिख सकता है। भारत से होने वाले कार निर्यात पर सीधा असर मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और सऊदी अरब के बाद भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा पैसेंजर व्हीकल निर्यात बाजार बन चुका है। कई वाहन निमार्ताओं के लिए यह सिर्फ एक विदेशी बाजार नहीं, बल्कि बिक्री और उत्पादन को स्थिर रखने वाला अहम गंतव्य है। भारत से मैक्सिको भेजी जाने वाली कुल कारों में लगभग आधी हिस्सेदारी स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन समूह की है। जबकि इसके बाद ह्यूंदै, निसान और मारुति सुजुकी का नंबर आता है। इनमें से ज्यादातर कारें छोटे इंजन वाली, एक लीटर से कम पेट्रोल क्षमता की होती हैं। जिन्हें खास तौर पर मैक्सिको के ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, न कि उत्तर अमेरिकी बाजार के लिए। यही वजह है कि भारतीय वाहन निमार्ता यह तर्क देते रहे हैं कि उनकी कारें मैक्सिको के घरेलू उद्योग से सीधे तौर पर प्रतिस्पर्धा नहीं करतीं।

कोठरी में इमरान खान को एकांत कारावास; यूएन विशेषज्ञ ने जताई चिंता, कहा- यह यातना के बराबर

जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र का यातना मामलों की विशेषज्ञ ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में स्थिति पर चिंता जताई और पाकिस्तान सरकार से कहा कि वह तत्काल और प्रभावी कदम उठाए। विशेषज्ञ ने कहा कि खान को दिन में 23 घंटे एकांतवास में रखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र की यातना मामलों की विशेषज्ञ एलिस जिल एडवर्ड्स ने आज पाकिस्तान सरकार से आग्रह किया है कि वह पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की जेल में स्थिति को लेकर आ रही रिपोर्ट्स पर तत्काल और प्रभावी कदम उठाए। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी परिस्थितियां यातना या अन्य अपमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के बराबर मानी जा सकती हैं। एडवर्ड्स ने कहा, मैं पाकिस्तानी अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने की अपील करती हूं कि इमरान खान की हिरासत की शर्तें पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और मानकों के अनुरूप हों। उन्होंने बताया कि 26 सितंबर 2023 को रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्थानांतरित होने के बाद से इमरान खान को लंबे समय तक एकांत कारावास में रखा गया है। उन्हें दिन में 23 घंटे कोठरी में बंद रखा जाता है और बाहरी दुनिया से उनका संपर्क बेहद सीमित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि खान को उनकी कोठरी में कथित तौर पर लगातार कैमरे की निगरानी में रखा जाता है। विशेषज्ञ ने इस बात पर जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत लंबे समय तक एकांत कारावास प्रतिबंधित है और अगर यह 15 दिनों से अधिक समय तक हो जाता है, तो इसे यातना का एक रूप माना जाता है। एडवर्ड्स ने कहा, इमरान खान के लिए एकांत कारावास की सजा को बिना किसी देरी के खत्म किया जाना चाहिए। यह न केवल एक गैरकानूनी उपाय है, बल्कि लंबे समय तक एकांत कारावास से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत हानिकारण परिणाम हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक, इमरान खान को कोठरी से बाहर गतिविधि करने या अन्य कैदियों से मिलने की अनुमति नहीं है और सामूहिक नमाज में भी शामिल नहीं हो सकते। वकीलों, परिजनों और अदालत की ओर से अधिकृत अन्य लोगों की मुलाकातें अक्सर रोक दी जाती हैं या समय से पहले खत्म हो जाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान एक छोटी सी कोठरी में रखा गया है, जिसमें प्राकृतिक रोशनी और पर्याप्त वेंटिलेशन नहीं है। इस कोठरी में गर्मियों और सर्दियों में तापमान चरम सीमा तक पहुंच जाता है और खराब हवा के कारण दुर्गंध और कीट-मकौड़े की समस्या होती है। इसके कारण उन्हें मतली, उल्टी और वजन कम होने की शिकायत रही है। एडवर्ड्स ने कहा, जो कोई भी कैदी है, उसके साथ मानवता और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। कैदी की उम्र और स्वास्थ्य स्थिति का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिसमें उचित सोने की व्यवस्था, जलवायु संरक्षण, पर्याप्त जगह, रोशनी, गर्मी और वेंटिलेशन शामिल हैं। इमरान खान (72 वर्षीय) को पहले से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जिसमें 2013 के एक हादसे में गंभीर रीढ़ की चोट और 2022 की हत्या के प्रयास में गोली लगना शामिल है।

'हम गरीब हैं, हमारे बच्चों को...', भारत में पकड़े गए पाकिस्तानी मछुआरों के परिवारों ने लगाई गुहार

कराची : भारत की समुद्री सुरक्षा ने सीमा पार करने के आरोप में 11 पाकिस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया, जिनमें दो नाबालिग शामिल हैं। ऐसे में अब पकड़े गए मछुआवों के परिवारों ने पाकिस्तान सरकार के माध्यम से भारत से उन्हें छोड़ने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि वे गरीब मछुआरे हैं और मछली पकड़कर ही रोजी-रोटी कमाते हैं। भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने भारतीय सीमा में प्रवेश करने के आरोप में इस हफ्ते 11 पाकिस्तानी मछुआरों को गिरफ्तार किया है। इनमें दो नाबालिग लड़के भी शामिल हैं। ऐसे में अब इन मछुआरों के परिवारों ने भारत और पाकिस्तान सरकार से उनकी रिहाई के लिए गुहार लगाई है। परिजनों का कहना है कि हम सभी लोग गरीब मछुआरे हैं और मछली पकड़कर ही अपना घर चलाते हैं। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से कहा है कि वह राजनयिक रास्ते से भारत से बात कर मछुआरों को छुड़ाने की कोशिश करे। गिरफ्तार मछुआरे गुलाम मुस्तफा के पिता अहमद ब्रोही ने बताया कि सभी मछुआरे कराची के इब्राहिम हैदरी नाम के एक मछुआरा गांव में रहते हैं। 'हम बहुत गरीब लोग हैं" गिरफ्तार मछुआरे गुलाम मुस्तफा के पिता अहमद ब्रोही ने आगे कहा कि हम बहुत गरीब लोग हैं। मछली पकड़कर ही रोजी-रोटी चलती है। पहले भी हम बहुत दुख झेल चुके हैं। सरकार से गुजारिश है कि कुछ करे। उन्होंने इस दौरान एक पुरानी घटना का जिक्र करते हुए कहा कि चार साल पहले भी उनके इलाके के तीन मछुआरे इसी तरह पकड़े गए थे और वे अब तक भारत की जेलों में बंद हैं। अब समझिए कैसे हुई गिरफ्तारी? मीडिया रिपोर्टस के अनुसार बुधवार को भारतीय तटरक्षक बल (कोस्ट गार्ड) ने इन 11 मछुआरों को पकड़ा। उनकी नाव गुजरात के जखाऊ इलाके के पास भारतीय समुद्री सीमा में पाई गई थी। हालांकि, सिंध फिशरीज विभाग की प्रमुख फातिमा मजीद ने कहा कि संभव है मछुआरे गलती से भारतीय सीमा में चले गए हों। इसके बाद फातिमा मजीद ने बताया कि अरब सागर में भारत और पाकिस्तान के बीच कोई साफ सीमा दिखाई नहीं देती, इसलिए अक्सर मछुआरे अनजाने में सीमा पार कर जाते हैं। उन्होंने कहा कि काजर क्रीक और सर क्रीक ऐसे इलाके हैं, जहां दोनों देशों के मछुआरे अक्सर पकड़े जाते हैं। ये इलाके गुजरात के पास पड़ते हैं। फातिमा ने कहा कि गरीब मछुआरों के लिए समुद्र में कोई सीमा नहीं होती। उन्हें सिर्फ अपने परिवार का पेट भरना होता है। नाबालिग बच्चों को छोड़ने की मांग इस बार पकड़े गए मछुआरों में 12 साल का जहीर और 15 साल का हबीब भी शामिल हैं। फातिमा मजीद ने भारत से अपील की कि कम से कम बच्चों को मानवीय आधार पर रिहा कर दिया जाए। गौरतलब है कि पाकिस्तान फिशरफोक फोरम के मुताबिक, इस ताजा गिरफ्तारी के बाद भारत की जेलों में बंद पाकिस्तानी मछुआरों की संख्या करीब 74 हो गई है। आमतौर पर भारत और पाकिस्तान समय-समय पर कैदियों की अदला-बदली करते रहते हैं, जिनमें ज्यादातर गरीब मछुआरे होते हैं। लेकिन पिछले साल से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के कारण यह प्रक्रिया धीमी पड़ गई है।

उत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मंडल रेल प्रबंधक (संकेत एवं दूरसंचार) उत्तर रेलवे, लखनऊ मंडल, लखनऊ द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्रो पर निम्नलिखित कार्य हेतु ई–निविदायें (सिंगल पैकेट सिस्टम) आमंत्रित की जाती है।

निविदा सं०	106-Sig-Tender-44-2025-26
कार्य का नाम : ''एस एंड टी वर्क इन कनेक्शन विथ रोड अंडर ब्रिज (1+1) ऐट एल0सी0 गेट्स इन जेड0 बी0 डी0–ए0वाई0सी0 सेक्शन ऑफ़ लखनऊ डिवीज़न ऑफ़ नॉर्थेर्न रेलवे।।''	
अनुमानित लागत	रु0 64,83,320.06
निविदा प्रपत्र की कीमत	निल
धरोहर राशि	रु0 1,29,700.00
कार्य पूरा करने की अवधि	270 दिन
निविदा दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	05.01.2026 15:30 बजे तक
वेबसाइट विवरण एवं नोटिस बोर्ड का स्थान जहाँ निविदा दस्तावेजों को देखा जा सकता है।	www.ireps.gov.in वरिष्ठ सिगनल एवं दूरसंचार अभियंता कार्यालय / म.रे.प्र. कार्यालय परिसर / उत्तर रेलवे / लखनऊ

ठेकेदारों को ई–निविदा सिस्टम में भाग लेने के लिए भारतीय रेलवे की वेब साइट www.ireps.gov.in के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य हैं।
- समस्त नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र में देखी जा सकती है।
- मैनुउल निविदायें स्वीकृत नहीं की जायेंगी।
- निविदा प्रपत्र एवं बयाना धनराशि का भुगतान सिर्फ नेट बैंकिग या पेमेंट गेटवे द्वारा स्वीकृत की जायेंगी।

निविदा सू० सं०–106–सिग–टेन्डर–44/2025–26 दिनांक: 11.12.2025

3852/2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे

ई–ऑक्शन सूचना

वरिष्ठ मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, उत्तर रेलवे, लखनऊ के द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई–ऑक्शन आमंत्रित किया जाता है।

एडमिन यूनिट/जोन	Lucknow-NR-Division-Commercial/Northern Railway
नीलामी सूची सं.	PYGS-SMU-25
कार्य का विवरण	Allotment of catering Stall at PYGS station of Lucknow Division, Northern Railway for the period of 05 years.
नीलामी सूची प्रकाशन तिथि	05.12.2025
नीलामी प्रारम्भ तिथि (समस्त लॉट)	22.12.2025 at 11:00 hrs.
नीलामी बन्द करने की तिथि व समय	22.12.2025 at 11:30 hrs.
वेबसाइट विवरण जहाँ पंजीकृत बोलीदाताओं द्वारा नीलामी का पूरा विवरण देखा जा सकता है।	E-Auction Module of www.ireps.gov.in

Details of catering stalls to be auctioned are as under:-

S. N.	Station	Lot No.	Stall ID	Close Date/ Time	Quota	Sub Quota
1	PRAYAGRAJ SANGAM	Catg-LKO-PYGS-SMU-42-24-1	PYGS/PF-1/104/ NEW	22.12.2025 at 11:30 hrs.	SMU	SC

3862/2025

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/सा., मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, हज़रतगंज, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निम्नलिखित कार्य के लिए खुली ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

1.	ई-निविदा सूचना सं. : 1185-वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता-उत्तर रेलवे-लखनऊ दिनांक 12.12.2025
2.	कार्य का नाम : माघ मेले के संबंध में लखनऊ मण्डल के प्रयाग और उसके आसपास के स्टेशनों पर अस्थायी बाहरी विद्युत सुविधाओं की व्यवस्था का प्रावधान।
3.	अनुमानित लागत : रु. 29,21,354/- (उनतीस लाख इक्कीस हज़ार तीन सौ चौवन रूपये मात्र)
4.	बयाना राशि : रु. 58,500/- (अठ्ठावन हज़ार पाँच सौ रूपये मात्र)
5.	कार्य पूर्ण करने की अवधि : 2 माह
6.	ई-निविदा फार्म जमा करने की अंतिम तिथि व समय तथा खोलने की तिथि : दिनांक 05.01.2026 को 15:00 बजे तक तथा खुलने का समय उसी दिन 15:30 बजे वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/सा., उत्तर रेलवे, हज़रतगंज, लखनऊ के कार्यालय में।
7.	प्रस्ताव की वैधता : ई–निविदा खुलने की तिथि से 60 दिन।
8.	उत्तर रेलवे की वेबसाइट : अतिरिक्त सूचना उत्तर रेलवे की वेबसाइट www.ireps.gov.in पर चेक की जा सकती है।

सं.: 1185-वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता-उत्तर रेलवे-लखनऊ दिनांक: 12.12.2025 3865/25

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

क्या खत्म हो जाएगा ट्रंप का भारत पर लगाया 50% टैरिफ? तीन अमेरिकी सांसदों ने उठाया यह बड़ा कदम

वॉशिंगटन डीसी। अमेरिकी संसद के निचले सदन में तीन सांसदों ने एक प्रस्ताव पेश किया है, जिसका मकसद डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से भारत पर लगाए गए पचास फीसदी टैरिफ को खत्म करना है। इससे पहले ब्राजील के लिए भी ऐसा ही प्रस्ताव पेश किया गया था। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के तीन सदस्यों ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को एक प्रस्ताव पेश किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा को खत्म करना है, जिसके तहत भारत से आयात पर 50 फीसदी तक टैरिफ लगाए गए थे। उन्होंने इन उपायों को 'गैरकानूनी' बताया। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ अमेरिकी श्रमिकों, उपभोक्ताओं और दोनों देशों के संबंधों के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं। यह प्रस्ताव सांसद डेबोरा रॉस, मार्क वीजी और राजा कृष्णमूर्ति के नेतृत्व में पेश किया गया है। यह कदम सीनेट में पेश किए गए एक द्विदलीय प्रस्ताव के बाद उठाया गया है, जिसका मकसद ब्राजील पर लगाए गए इसी तरह के टैरिफ को समाप्त करना और टैरिफ बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा आपातकालीन शक्तियों के उपयोग को सीमित करना है। सांसदों के कार्यालयों की ओर से जारी बयान के मुताबिक, यह प्रस्ताव 27 अगस्त 2025 को भारत पर लगाए गए अतिरिक्त 25 फीसदी 'द्वितीयक' टैरिफ को वापस लेने की मांग करता है। यह टैरिफ पहले से लगे पारस्परिक टैरिफ के ऊपर लगाया गया था, जिससे अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (आईईईपीए) के तहत कई भारतीय उत्पादों पर कुल टैरिफ 50 फीसदी तक पहुंच गया था। तीन सांसदों ने भारत पर लगे टैरिफ पर क्या कहा? कांग्रेस सदस्य रॉस ने कहा, नॉर्थ कैरोलिना की अर्थव्यवस्था व्यापार, निवेश और एक सक्रिय भारतीय-अमेरिकी समुदाय के जरिये भारत से गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय कंपनियों ने राज्य में एक अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया है, जिससे जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा हुई हैं, जबकि नॉर्थ कैरोलिना के निमार्ता हर साल सैकड़ों मिलियन डॉलर का सामान भारत को निर्यात करते हैं। सांसद वीजी ने कहा, भारत एक अहम सांस्कृतिक, आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है और ये अवैध टैरिफ आम उत्तरी टेक्सस के लोगों पर एक कर की तरह हैं, जो पहले से ही बढ़ती लागत से जूझ रहे हैं। वहीं, भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये टैरिफ उलटा असर डालने रहे हैं, आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित कर रहे हैं, अमेरिकी श्रमिकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उपभोक्ताओं के लिए लागत बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जोर दिया कि इन्हें खत्म करने से अमेरिका-भारत आर्थिक और सुरक्षा सहयोग मजबूत होगा।

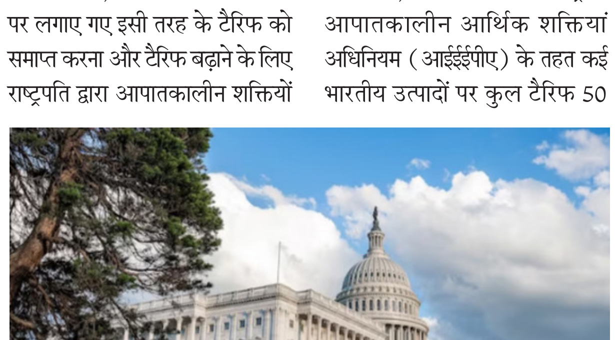

दक्षिण अफ्रीका में निमार्णाधीन मंदिर गिरने से दो लोगों की मौत; मलबे में कई लोग फंसे

डरबन : दक्षिण अफ्रीका में एक निमार्णाधीन मंदिर के गिरने से दो लोगों की मौत हो गई है। अभी भी मलबे में कई लोगों को दबे होने की आशंका है। फिलहाल मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए बचाव कार्य चल रहा है। दक्षिण अफ्रीका के डरबन के उत्तर में स्थित रेडक्लिफ इलाके में शुक्रवार दोपहर को चार मंजिला मंदिर गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। मलबे में कई लोग दबे हैं, जिन्हें बचाने के लिए अभियान चल रहा है। मुश्किल हालात के बीच, मलबे में सावधानी से ड्रिल करके जिंदा लोगों को ढूंढने की कोशिश हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक मजदूर की हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कंक्रीट का एक ढांचा मंदिर पर डाला जा रहा, जिससे पूरा ढांचा गिर गया और पूरी साइट गिर गई।

पूर्वोत्तर रेलवे

ई-निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरिष्ठ मण्डल विद्युत इंजीनियर/टी.आर.एस./पूर्वोत्तर रेलवे, लोको शेड, गोण्डा द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु खुली ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है:–

निविदा सूचना संख्या एवं कार्य का नाम

क्रम सं.-01, निविदा सूचना संख्या: LS-GD-2025-Ovh-Aux-Conv, कार्य का नाम: ''लोको शेड, गोण्डा में 01 वर्ष के लिये पारंपरिक विद्युत इंजनों की सहायक मोटरों की मरम्मत और ओवरहालिंग।'' अनुमानित लागत (रू.में): ₹48,26,348.48, निविदा की अवधि: 12 माह, अग्रिम धनराशि (रू.में): ₹96,500/-

♦ ऑफर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय: 03-01-2026, 12:00 बजे। ♦ इस ई-निविदा से संम्बंधित विस्तृत जानकारी, न्यूनतम अर्हतायें तथा नियम एवं शर्तें, रेलवे की वेबसाईट *www.ireps.gov.in* पर उपलब्ध है। ♦ निविदाकार ई-निविदा प्रपत्र को अपलोड करने से पूर्व इस ई-निविदा से संम्बंधित शुद्धि पत्र (यदि कोई हो) को वेबसाईट पर संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

नोट:- (1) इस ई-निविदा के विरूद्ध मैनुअल ऑफर स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे प्राप्त मैनुअल ऑफर को उपेक्षित कर दिया जायेगा। **(2)** विस्तृत विवरण व निविदा जमा करने हेतु कृपया भारतीय रेलवे की वेबसाईट *http://www.ireps.gov.in* को देखें।

मंविइं/टीआरएस, लोको शेड, गोण्डा

मुजाधि/विद्युत-214

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

ट्रंप के संघर्ष रोकने का दावा फेल, थाई सेना ने सीमा पर फिर बरसाए बम; इमारतें-पुल तबाह

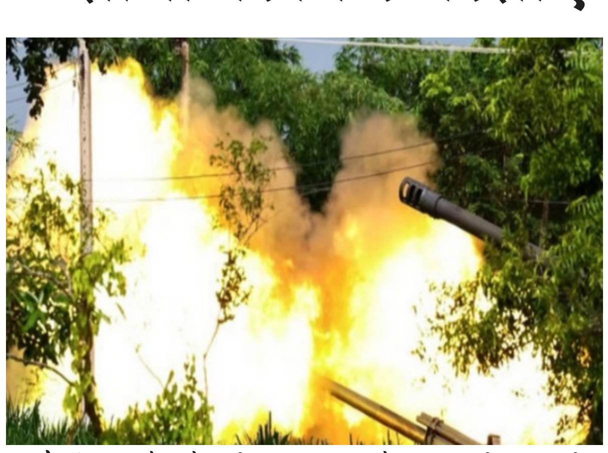

बैंकॉक : थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। शनिवार को थाई वायुसेना ने दो ऋ-16 लड़ाकू विमानों से कंबोडिया सीमा के पास हवाई हमला किया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीज जारी सीमा संघर्ष में आयदिन नए-नए मोड़ सामने सामने आ रहे है। एक तरफ जहां बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि वो एक फोन पर ये संघर्ष रुकवा देंगे। वहीं दूसरी ओर ताजा अपडेट ये है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर हमले और तेज होते नजर आ रहे हैं। आज यानी शनिवार को भी थाईलैंड की सेना ने कंबोडिया सीमा के पास हवाई हमला किया। जानकारी के मुताबिक, थाई वायुसेना ने दो एफ-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करते हुए कई ठिकानों पर बम गिराए। मीडिया रिपोर्टस की माने तो स्थानीय समयानुसार शनिवार की सुबह 5:50 बजे, थाई सेना ने कंबोडिया के पश्चिमी प्रांत बट्टमबोंग के त्मोर दा शहर के एक होटल की इमारत को निशाना बनाकर एक बम गिराया। इसके पांच मिनट बाद, 5:55 बजे उसी इलाके में एक और होटल इमारत पर बमबारी की गई। होटल के बाद पुलों को थाई सेना ने बनाया निशाना इस हमले के बाद थाई सेना के हमले का रुख पुलों की ओर हो गया।

पूर्वोत्तर रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से वरि० मण्डल यॉत्रिक इंजीनियर/समाडि/स०, पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु बिड सिस्टम आधारित खुली ई-निविदायें आमंत्रित की जाती है।

निविदा सूचना संख्या एवं कार्य का नाम : निविदा सूचना संख्या : 16-2025-CW, ''प्रोविजन फॉर रिक्लेमेशन, रिपेयर, पेंटिंग एण्ड फिटमेन्ट ऑफ फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक (एफआरपी) नोज कोन कपलर कवर एण्ड एफआरपी साइड वॉल्स ऑफ डीटीसी यूनिट ऑफ वन्दे भारत ट्रेन्स ऐट गोरखपुर, ऐशबाग एण्ड गोमतीनगर कोचिंग डिपो फॉर ए पीरियड ऑफ 24 मन्थ्स''। अनुमानित लागत (रू० में) : रू० 43,45,785.58, अग्रिम धन (रू० में) : रू० 86,900.00, निविदा की अवधि- 24 मन्थ्स। ● ई-निविदा प्रपत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय 06.01.2026, 15:00 बजे तक एवं यह ई-निविदा दिनांक 06.01.2026 को 15:00 बजे के बाद खोली जायेगी। ● इस ई-निविदा से सम्बंधित विस्तृत जानकारी, न्यूनतम अर्हतायें तथा नियम एवं शर्तें, पूर्वोत्तर रेलवे की वेबसाईट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है। ● निविदाकार ई-निविदा प्रपत्र को अपलोड करने से पूर्व इस ई-निविदा सूचना से संबंधित शुद्धि पत्र (यदि कोई हो) को वेबसाईट पर संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

वरि० मण्डल यॉत्रिक इंजीनियर/समाडि/स० पूर्वोत्तर रेलवे, लखनऊ

मुजाधि/यांत्रिक-106

गाड़ियों की छतों व पायदान पर कदापि यात्रा न करें।

पूर्वोत्तर रेलवे

खुली ई–निविदा सूचना संख्या NER-BSB0SnT-OT-27-2025

मण्डल रेल प्रबन्धक/सिग. एवं दूरसंचार/पूर्वोत्तर रेलवे/वाराणसी कृते एवं भारत के राष्ट्रपति की ओर से निम्नलिखित कार्यो के लिये ''खुली ई–निविदा''आमंत्रित की जाती है :–

क्रमांक-1, निविदा सूचना संख्या एवं कार्य का नाम: NER-BSB0SnT-OT-27-2025: कार्य का नाम: व.म.सि.दू.इ-II/वाराणसी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पुराने सिग्नलिंग और खराब हो चुके एसेट्स (ईपीएम ग्राउंड कनेक्शन, आईपीएस बैटरी सेट, ट्रैक बैटरी और अन्य विविध वस्तुयें) के बदलाव साथ–साथ टेक्निकल एडवाइजरी नोट के अनुसार प्रत्येक बीपीएसी यूनिट के लिये पृथक पॉवर सप्लाई अरेंजमेंट के प्रावधान का कार्य। **विवरण:** अनुमानित लागत (रू० में): ₹ 1,35,40,276.85, बयाना की राशि (रू० में): ₹ 2,17,700/-, निविदा प्रपत्र की कीमत: ₹ 00.00, कार्य पूर्ण करने की अवधि: 08 माह, निविदा बंद होने की अंतिम तिथि एवं समय: 05-01-2026 को 15:00 बजे।

(1) ई–निविदा दिनांक 05-01-2026 को 15:00 बजे तक आन लाईन जमा किया जा सकेगा। (2) पूर्ण विवरण की जानकारी प्राप्त करने एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिये भारतीय रेलवे की वेबसाईट i.e. *www.ireps.gov.in* देखें।

मण्डल रेल प्रबन्धक/सिंग. एवं दूरसंचार वाराणसी

मुजाधि/सिगनल-73

गाड़ियों की छतों व पावदान पर कदापि यात्रा न करें।

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063787346044 **Twitter:** https://twitter.com/mantrabharat?t=8tJONQ7H-h6EKqqap2tVMw&s=08 **Mobile No:** 7007837917

मंत्र भारत : R.N.I. UPHIN/2016/67511 स्वात्वाधिकारी राकेश शर्मा के लिए राकेश शर्मा द्वारा दीक्षित प्रिंटिंग प्रेस 120/51/1 मॉडल हाउस लखनऊ से मुद्रित एवं 233जी इंद्रलोक कॉलोनी कृष्ण नगर लखनऊ से प्रकाशित।

E-Mail : mantralko1008@gmail.com | सम्पादक : राकेश शर्मा, मोबाइल : 7007837917 | वैधानिक सूचना : मंत्र भारत से संबंधित समस्त विवाद निपटारे का क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।